चिंतन

खाद्य महंगाई से लोग बेहाल, इसे रोके सरकार

नवरात्र- दशहरा बीता है, आगे दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहार हैं, इससे पहले महंगाई चरम की ओर है। खासकर सब्जियों व फलों के दाम आसमान पर हैं। सब्जियों की महंगाई दर 11 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदा हो गई है। खाद्य महंगाई के लगातार उच्च रहने के चलते आम लोगों की हालत पहले से ही पतली है, त्योहार के समय अगर उसमें तड़का लग जाय तो पर्व का जायका और बिगड़ जाता है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में तगड़ा इजाफा हुआ है। खाने-पीने के चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.49 फीसदी पर पहुंच गई। यह 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। इससे पिछले महीने अगस्त में यह 3.65 प्रतिशत पर थी। खुदरा मुद्रास्फीति बीते वर्ष के सितंबर माह में 5.02 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई दर पिछले महीने दर्ज किए गए 5 साल के निचले स्तर 3.65 फीसदी से कहीं अधिक है। जुलाई के बाद पहली बार खुदरा महंगाई दर आरबीआई की ओर से तय किए गए लक्ष्य 4 प्रतिशत को पार कर गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बास्केट में आधी हिस्सेदारी रखने वाले खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सितंबर में 9.24 फीसदी पर पहुंच गई। अगस्त में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 5.66 प्रतिशत थी। अगस्त 2023 में सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर 6.83 प्रतिशत थी। इससे पहले थोक महंगाई के आंकड़े भी जारी हुए। सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के ही महंगे होने से थोक मूल्य मुद्रास्फीति भी सितंबर में बढ़कर 1.84 फीसदी हो गई। अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 1.31 फीसदी थी। पिछले साल सितंबर में यह 0.07 फीसदी घटी थी। थोक खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.53 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त में यह 3.11 फीसदी थी। इस तरह थोक और खुदरा दोनों महंगाई दर में वृद्धि के पीछे खाने-पीने की ही महंगाई जिम्मेदार है। सरकार खाद्य महंगाई रोकने में विफल रही है। अक्सर त्योहारी सीजन में खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। इसके पीछे कालाबाजारी, जमाखोरी अधिक जिम्मेदार हैं। लहसुन, अदरख, टमाटर, प्याज जैसी चीजें वर्ष भर महंगे बिक रहे हैं, जबकि इनकी उपलब्धता में कमी कभी नहीं आई। यह एक पैटर्न है देश में, पर राज्य सरकारें आंखें मूंदी रहती हैं। सरकार कभी यह देखने की जहमत ही नहीं उठाती कि स्थानीय बाजार में खाने-पीने की चीजें महंगी क्यों बिक रही हैं? जबकि उत्पादक किसानों को इतना मूल्य नहीं मिलता। लागत और लाभ का मैकेनिज्म सरकारी स्तर पर तय नहीं होने से मूल्यों पर नियंत्रण करना कठिन होता गया है। खाद्य बाजार पर बिचौलियों व थोक विक्रेताओं की मनमानियों का कब्जा बना रहता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई थामने का जिम्मा देकर अपने दायित्वों से जैसे इतिश्री कर ली है। यह साफ हो चुका है कि भारत में महंगाई के पीछे सरकार का नीतिगत मसला अधिक है, मौद्रिक कम है। केवल मौद्रिक नीति से महंगाई नियंत्रण संभव नहीं है। यह उपाय सहायक हो सकता है, पर खाद्य महंगाई पर पूर्ण लगाम सरकार ही नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक सजगता से लगा सकती है। उच्च महंगाई का असर अंततः समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के मकसद से ही पिछले सप्ताह पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई कम हो रही है, कमेटी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई अनुमान को 4.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा था। फिर भी खाद्य महंगाई कम नहीं रही है। इसे रोकने के लिए सरकार को त्वरित कदम उठाना चाहिए।

विश्लेषण
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट और विचार मंथनों में भारत में शोध और नवाचार की अहमियत प्रस्तुत की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य, उद्योग, कारोबार, कृषि, संचार, रक्षा, शिक्षा और अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में विकास के परिप्रेक्ष्य में शोध और नवाचार की प्रमुख भूमिका है तथा भारत को विकसित बनाने में भी शोध और नवाचार में और तेजी से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है।

शोध-नवाचार से विकास को गति

इन दिनों प्रकाशित हो रही भारत के विकास से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट और विचार मंथनों में भारत में शोध और नवाचार की अहमियत प्रस्तुत की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य, उद्योग, कारोबार, कृषि, संचार, रक्षा, शिक्षा और अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में विकास के परिप्रेक्ष्य में शोध और नवाचार की प्रमुख भूमिका है तथा भारत को विकसित बनाने में भी शोध और नवाचार में और तेजी से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जो भारत जीआईआई रैंकिंग में 2015 में 81वें स्थान पर था, अब वह 39वें स्थान पर पहुंच गया है। जीआईआई रैंकिंग में भारत की प्रगति दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। इस ऊंची रैंकिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम की उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि जीआईआई 2024 के तहत भारत निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है भारत मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) क्लस्टर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है।

भारत के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में सूचीबद्ध हैं और भारत अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर है। जीआईआई 2024 के अनुसार, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके दुनिया की सबसे अधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर आने वाले देश हैं। यदि हम बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों को भी देखें तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। निःसंदेह शोध एवं नवाचार तथा बौद्धिक सम्पदा की दुनिया में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत आईटी सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के उद्योग-कारोबार तेजी से समय के साथ आधुनिक हो रहे हैं। विगत अगस्त माह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खेतों में जाकर जारी की गई 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से कृषि नवाचार का नया अध्याय लिखा गया है। निश्चित रूप से शोध एवं नवाचार के मद्देनजर भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता जैसे विविध क्षेत्रों में

अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही भारत में घरेलू कारोबार में सरलता, विदेशी निवेश, जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। भारत की शोध एवं नवाचार ऊंचाई में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधीकरण, हाइटेक विनिर्माण और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ-साथ अटल इनोवेशन मिशन ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारत बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्वदेश में विकसित लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत के तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। सुपरकंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर तैयार किए गए हैं। इन सुपरकंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं। इनके आधार पर किसी देश में विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजी से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की है। यद्यपि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में आरएंडडी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसदी शोध एवं विकास में व्यय किया जाता है।

ऐसे में हमें भारत को ऊंचाई देना होगा कि कोई 6-7 दशक पहले अमेरिका ने आरएंडडी पर तेजी से अधिक खर्च करके सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवाओं, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है। हमें अपने औद्योगिक ढांचे में बदलाव लाना होगा, अपनी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बदलाव को आकार देना होगा। हम उम्मीद करें कि सरकार डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा प्रकाशित जीआईआई 2024 के तहत प्राप्त 39वीं रैंकिंग को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। साथ ही देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा देश के तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक कल्याण के मद्देनजर बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार पर अधिक धनराशि व्यय करने की ढर पर आगे बढ़ा जाएगा। इससे जहाँ ब्रांड इंडिया और मेड इन इंडिया की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ता दिखेगा। हम उम्मीद करें कि देश को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर सरकार और उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा बौद्धिक संपदा, शोध और नवाचार की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा आर्थिक सामाजिक विकास के नए अध्याय लिखने की डगर पर आगे बढ़ा जाएगा।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख शैविक स्थलों में शामिल है और अपने सुविख्यात मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीकालाहस्ती दक्षिण भारत के अत्यंत भोले नाथ के स्थलों में से एक माना जाता है। श्रीकालाहस्ती अलावा शिव के पंच भूतों में से एक के लिए प्रसिद्ध है।

पुरस्कार

डॉ. एस.डी. वैष्णव

'हिबाकुशा' के संगठन को शांति का नोबेल, बड़ा संदेश

इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कारजापान के हिबाकुशा लोगों के संगठन 'निहोनहिडानक्यो' को दिया गया है। 'हिबाकुशा' जापान में परमाणु बम के हमले में बच गए उन लोगों का समूह है, जिन्होंने आगे चलकर 1954 में इस संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की कल्पना करना है। अपनी स्थापना के लगभग 70 वर्षों बाद इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना विश्व शांति में मील का पत्थर साबित होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक का समय विश्व इतिहास में मानव त्रासदी की गाथा के रूप में याद किया जाएगा। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच युद्ध का ऐसा तांडव मचा कि उस वक्त दुनिया की आबादी के लगभग तीन प्रतिशत लोग मारे गए। महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उत्थान इस विश्व युद्ध का परिणाम था। महाशक्तियों ने आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता का इस युद्ध में परिचय दिया। यूएसए ने अपनी वैज्ञानिक उन्नति परमाणु हथियार के रूप में पहली बार जापान को दिखाई। 1941 में जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्लहार्बर पर हमला किया था जिसका उत्तर अमेरिका ने 1945 में परमाणु हमले के रूप में दिया,जो मानवता के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। जापान के दोनों हंसते-खेलते शहर हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में विनाश के गर्भ में समा गए। 6 अगस्त 1945 का दिन, जब अमेरिकी वायु सेना ने जापान के शहर हिरोशिमा पर बी-29 बमवर्षक विमान मालागेस 'लिटिल बॉय' और इसके ठीक तीन दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बी-29 बमवर्षक विमान बॉक्सकार से 'फैटमैन' नमक परमाणु बम गिराया। इस विस्फोट से शहर के केंद्र से पांच वर्ग मील का क्षेत्र राख में तब्दील हो गया। डेढ़ लाख के करीब लोग मारे गए और इस महाविनाश के बाद अंततः जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस एटमी विध्वंस के बाद रेडिएशन और घावों से कई लोगों की मौतें और हुईं। जो बच गए वे अपंगता के शिकार हुए। आज भले ही हिरोशिमा और नागासाकी अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन परमाणु विस्फोट का दंश ऐसा था कि स्थानों बाद भी वहाँ के लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और रेडिएशन के कई अन्य प्रभावों का सामना करना पड़ा। इस महाविनाश की गाथा को 79 वर्ष बीत गए हैं। युद्ध के अमिट निशान वहां के निवासियों के जेहन में अब भी संचित हैं। इजरायल-ईरान तनाव के बरक्स एटमी विध्वंस का जो खतरा आज दुनिया के सामने गहरा रहा है, ऐसे में हमें अतीत से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसका दंश बहुत ही कारुणिक और हृदय विदारक होता है। आज जब दुनिया महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। हथियारों की होड़ मची हुई है। ऐसे में हमें हिबाकुशा और उनके संगठन 'निहोनहिडानक्यो' की प्रशंसा करनी चाहिए, जो सालों से विश्व शांति की कामना के लिए प्रयासरत हैं। विश्व शांति के इस नोबेल पुरस्कार के साथ ही यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि पूरा विश्व समुदाय एटमी विध्वंस के खतरों से हमेशा बचा रहेगा और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया में मनुष्यता के लिए जगह हमेशा बची रहेगी।

(लेखक स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अहिंसा के प्रयोग

संकलित
दर्शन

हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या इसके प्रभाव को कम करना, समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। हिंसा अनेक तरह की हो सकती है। शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त यह मानसिक, शाब्दिक या परोक्ष भी हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना, जिससे भय एवं आतंक की छाया में जीवन हर समय आशंकित हो, अव्यवस्थित हो-अप्रत्यक्ष हिंसा है। इसलिए प्रत्येक हिंसा का शमन ही मानव के लिए हितकारी है। हिंसा किसी पशु या अमानुष का विषय हो सकती है, परंतु मानव का धर्म कतई नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्मः, यही सत्य वचन है। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। अहिंसा सभी समस्याओं का हल है। लोगों के मन के भीतर प्रेम का बीज होता है, घृणा का फल नहीं। सावधानी से आदर्श व्यवहार का धैर्यपूर्वक पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती। किसी विवाद के उत्पन्न होने से शांति के लिए सदैव एक राह शेष रहती है, इस तथ्य को गांठ बांध लेना चाहिए। बातों से रास्ता निकलता है। संवेदनहीनता से मानवता का मार्ग अवरुद्ध होगा। आप भगवान को मानें या न मानें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे आपका महत्व अवश्य बढ़ेगा या घटेगा। इसी तरह प्रकृति के विषय में सार्थक सोच होना चाहिए। नैतिकता के पाठों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा तो मानवता के लिए विष के समान है। अहिंसा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति शांति के सच्चे नायक हैं। जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र सबसे उपयोगी तंत्र बन सकता है।

पांच मिनट का जीवन

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गये वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहीं लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरें में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

अंतर्मन

आज की पाती

तनाव कम करें, खुशियों की तलाश करें

आज भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में हम इतना तेज गति से दौड़ रहे हैं कि यह अंधी दौड़ हमें बेवजह का तनाव देकर खुशियों से दूर कर रही है। आज लगभग सभी बीमारियों का एक कारण तनाव भी है और हमारे देश में मानसिक रोगियों की संख्या भी कम नहीं होगी। हमारे पास सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, विभिन्न टेंशनों के मकड़जाल में हमारा मन हर वक्त घिरा रहता है, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण हमारे खानपान को भी डॉक्टरों ने सीमित कर दिया है और रात को नींद किसी कारण न आती हो, तो हमारे पास जितनी भी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में हैं, वो सब बेकार हैं। हमें तनाव दूर कर खुशियों की तलाश करनी चाहिए।

– राहुल छाबड़ी, रायगढ़

टेंड

दिल्ली पुलिस को बधाई

जो दिल्ली पुलिस वो 13,000 करोड़ रुपये वर्ष इनसे जुड़े मामले के सफल ऑपरेशनों वर्ष वृद्धाल के लिए बधाई देता हूं, जिसने हाल ही में कुख्यात पुलिस द्वारा 5,000 करोड़ रुपये वर्ष वर्कवीक कंपाट्स वरना की शामिल है।

-अमित शाह, केंद्रीय मंत्री

स्वास्थ्य मंत्रियों का आभारी

लेवजो वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने वर्ष जिम्मेदारी है और उन्हें वह पालन व्यावहारिक तरीके से करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्रियों का आभारी हूं

-टेड्रोस, महानिदेशक डब्ल्यूएचओ

मेहनत रंग लाती है

तुरुछ वरुणावर आपके जहान में होते हैं। बापान वर्ष वार्ता में होते हैं और फिर आपकी मेहनत आपके उभार्य कारण से लगातार छपा वर वेती है। जो वॉलेज के जमाने के स्टार विशेषज्ञ पार्टनर के ना तुम्हें के पंडाल में जबरदस्त बहुत अच्छा लगा।

-अनुपम खेर, अभिनेता

स्टारशिप बूस्टर का निरीक्षण

अभी स्टारशिप बूस्टर का निरीक्षण किया गया है, जिसे अब हवियरों ने अपने लॉन्च माउंट से वापस रवा दिया है। अच्छा लग रहा है! कुछ बहतीं इजल ओजल लीटिंग और कुछ अन्य छोटी समस्याओं के समाधान विकसा हो जाते हैं, लैंडिंग इन्जंड आसानी से ठीक कर लिख जाता है।

-एलन मस्क, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए 40 हजार भारतीयों के आवेदन

ऑस्ट्रेलिया के सहायक आव्रजन मंत्री मैट थिस्टलेथवेट ने सोमवार को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के नए 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत 1,000 स्थानों के लिए केवल दो सप्ताह में लगभग 40,000 आवेदन जमा हुए हैं। थिस्टलेथवेट ने उक्त कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आयोजित समारोह में कहा कि यह वीजा 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों को 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वीजा प्रक्रिया एक अक्टूबर को शुरू हुई और महीने के आखिर में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद, बिना किसी ड्रामे के (रैंडम तरीके से) आवेदनों में से सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और सुने गए उम्मीदवार अगले वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में अपना प्रवास शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह वीजा भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में खुद को शामिल करने का और अनेक क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। थिस्टलेथवेट ने कहा, ' वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीजा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप जो काम कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ऑफ बीट

क्या तोता पालन से वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा होती है?

विश्वभर में आज तोतों की लगभग 400 प्रजातियां हैं और इनका करीब एक तिहाई हिस्सा विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। इनमें से विलुप्तप्राय अफ्रीकी ग्रे तोता भी शामिल है। आम तौर पर यह पक्षी पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका के कई हिस्सों में पाया जाता था लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आती गई। घाना में 1990 के दशक की शुरुआत से इसकी आबादी 99 प्रतिशत से घटकर 90 प्रतिशत तक हो गई है। हाल के वर्षों में बढ़े व्यावसायिक खामें उभरे हैं, जिनमें पालतू पक्षियों के रूप में बिक्री के लिए तोतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका अब तोतों का दुनिया में अग्रणी निर्यातक है। देश ने 2020 से मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में 120 से अधिक प्रजातियों के दस लाख से अधिक तोतों का निर्यात किया है। फिर भी उद्योग के तीव्र विकास के बावजूद इसके विस्तार को रोकने के लिए मौजूदा कानून के प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं। वन्यजीव व्यापार और तोतों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने में दशकों बिताने वाले शोधकर्ताओं के रूप में हमने मौजूदा मुद्रित सामग्री की गहन समीक्षा की ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि तोता पालन जंगली तोतों के संरक्षण के प्रयासों को कैसे प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 15 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

ढोल में पोल न हो

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधीकरण बुजुर्गों के लिए अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता का आंकलन कर रही है। इससे तकरीबन साढे चार करोड़ परिवारों के छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। यह आवेदन आधारित योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पोर्टल या आयुष्मान एप पर पंजीकरण करना होगा। 70 या उससे अधिक उम्र वाला हर बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने व तथा विस्तारित योजना शुरू होने पर सूची वाले किसी भी अस्पताल में पांच लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के पात्र होंगे। पहली सितम्बर तक साढ़े बारह हजार से अधिक निजी अस्पतालों समेत 29,648 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचिबद्ध किया जा चुका है। वर्तमान में दिल्ली, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है। जो लोग पहले से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं, पूर्वसैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र बल का लाभ उठा रहे हैं, वे दोनों में विकल्प चुन सकते हैं। आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा से गंभीर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा व आयुष्मान जैसी सुविधाओं की शुरुआत का उद्देश्य किफायती दर पर सबको इलाज मिलने की व्यवस्था उन्होंने ही दी है। हालांकि जितना इसका प्रचार किया गया, यह उतनी सफल नहीं हो पाई। खासकर देश के पिछड़े राज्यों व इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओंको उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि इस नई योजना के तहत अस्पतालों की संख्या काफी बढाई गई है। वरना अब तक लोगों को अपने मरीज को लेकर बड़े कस्बों या नजदीकी शहर की तरफ भागना पड़ता रहा है। दवाओं और निजी अस्पतालों के मोटे-मोटे बिलों को चुकाने लायक सामर्थ्य अभी अपने यहां बड़े वर्ग की नहीं है। जिन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों से लेकर गंभीर रोगों का इलाज कराने के लिए परिवार का मुंह ताकना पड़ता है। इस योजना के चलते उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो अपने बुजुर्गों के इलाज में पैसों की कटौती करने को मजबूर है, अब उनका बेहतर इलाज करवा सकेगा। परंतु महत्त्वपूर्ण तथ्य याद रखना होगा कि इन अस्पतालों में दवाओं, चिकित्सकों व सहयोगी कर्मचारियों का अकाल न रहने पाए। वरना योजनाओं का लाभ बुजुर्गों को प्राप्त नहीं हो सकता।

प्रदूषण के साये में दिल्ली

सर्दी आने से पहले ही राजधानी दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण फैलना वाकई चिंता का सबब है। कुछ दिन पहले तक पराली जलाने की घटना से दिल्ली-एनसीआर की हवा में जहर घुला था, और अब दशहरा में आतिशबाजी जलाने के बाद हालात और ज्यादा विकट हो गया है। दशहरा उत्सव के एक दिन बाद रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि महामारी वर्ष को खत्म करना, 2015 के बाद अक्टूबर से दिल्ली के लिए 'खराब' वायुयान वाले दिन का यह सबसे देरी से आगमन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े के, शहर का एयरोस्पेस मशीनरी (एक्यूआई) जो एक दिन पहले 'मध्यम' श्रेणी में था, रविवार को 224 पर पहुंच गया। 2023 में 6 अक्टूबर की शुरुआत में 212 का 'खराब' एक्यूआई देखा गया था। दरअसल, दिल्ली और इससे सटे शहरों में ठंड की दस्तक के समय से ही प्रदूषण होने लगता है। यह हर बार की कहानी है। लाख कोशिशों और सरकार की सख्ती के बावजूद न तो किसानों ने पराली जलाना रोका है और न लोगों ने आतिशबाजी। और इस तरह की जिद अगर नहीं रुकी तो राजधानी के लोगों को साफ-सुथरी हवा मयस्सर नहीं होने वाली। सरकार को अब ज्यादा संजीदगी से काम करना होगा। साथ ही यह जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण की दुश्वारियों को समझे और इसके प्रति लोगों को जागरूक करे। प्रदूषण का प्रहार किस कदर घातक है यह आंकड़ों को देखकर सहज रूप से समझा जा सकता है। लैसेट प्लैनिटेरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। दिल्ली सहित देश के 10 शहरों में प्रतिवर्ष हवा में पीएम 2.5 की अधिकता के कारण लगभग 33, 000 लोगों की मौत हो रही है। इसमें सिर्फ दिल्ली में 12 हजार लोग की जान जा रही है, यह प्रतिवर्ष होने वाली कुल मौत का 11.5 प्रतिशत है। देश के स्वच्छ वायु मानदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के दिशा निर्देश से चार गुना अधिक है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण के लिहाज से बेहतर माने जाने वाले शहरों में भी लोगों की जान जा रही है। हमें अभी से इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने की जिम्मेदारी सामूहिक है।

डॉ. कलाम जयंती/ श्वेता गोयल

करोड़ों के प्रेरणास्रोत

मिसाइलमैन' के नाम से विख्यात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम) भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, जो वैज्ञानिक थे। सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे विलक्षण गुणों की मिसाल डॉ. कलाम देश के महान वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक अद्भुत इंसान और एक प्रेरणादायक नेता भी थे, जिन्होंने अपने इन्हीं गुणों की बदौलत समस्त देशवासियों का दिल जीत लिया था क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिवेश में ऐसे गुणों वाले व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है।

भारत के बच्चों के भविष्य को लेकर वे चिंतित स्वर में कहते थे कि देश में प्रतिवर्ष दो करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, उन सभी बच्चों का क्या भविष्य होगा और जीवन में उनका क्या लक्ष्य होगा? क्या हमें उनके भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने चाहिएं या हमें उन्हें उनके नसीब के सहारे छोड़ अभिजात्य वर्ग के फायदे के लिए ही काम करना चाहिए? डॉ. कलाम का मानना था कि यदि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्क वालों का देश बनाना है तो इसमें समाज के तीन लोग सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, पिता, माता और गुरु। कलाम साहब का मानना था कि भारत 2020 तक युवाओं के योगदान की बदौलत एक विकसित देश बन जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उनके इस विजन को पूरा होने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है।

कलाम साहब कहा करते थे कि दुनिया हमें तभी याद रखेगी, जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और विकसित भारत देंगे, जो आर्थिक सम्पन्नता और सांस्कृतिक विरासत से मिला हो। उनका कहना था कि जो लोग अपने दिल से कार्य नहीं करते, वे जिंदगी में भले ही कुछ भी हासिल कर लें लेकिन वह खोखला होता है, जो उनके दिल में कड़वाहट भरता है। कलाम साहब के अनुसार जिंदगी कठिन है और आप तभी जीत सकते हैं, जब आप मनुष्य होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार के प्रति सजग हों। किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो उसे सफलता की खुशी का अहसास ही नहीं होगा।

जम्मू-कश्मीर का परिदृश्य

सामयिक

अवधेश कुमार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके पूर्व की राजनीतिक ध्वनि में अंतर है। चुनाव पूर्व भड़काऊ बातें करने वाले फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चुनावी रणनीति में आक्रामक होकर अधिकाधिक सीटें लाओ और फिर शुतुरमुर्ग की तरह सिमट कर शासन चलाओ। चुनाव की घोषणा से लेकर अभियान तक यह साफ हो गया था कि जम्मू क्षेत्र में भाजपा प्रभावी है लेकिन कश्मीर में उसका जनाधार नहीं बढ़ा है।

दूसरी ओर नेशनल कांफ्रेंस का जनाधार कश्मीर के साथ जम्मू क्षेत्र में भी है। हालांकि जम्मू के 43 में से भाजपा को 29 सीटें मिलने से उनके समर्थकों को निराशा हो सकती है। सच्चाई व जमीनी वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। वैसे तीन-चार सीट भाजपा काफी काम अंतर से हारी है। चूंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने एवं संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था इसलिए भी इसको इसके परिणाम के देखने के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। भाजपा समर्थको एवं कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के स्वाभाविक विरोधियों के अंदर निराशा इसलिए है कि वहां के लोग ही खुलकर बता रहे थे कि 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने जितना विकास किया उसकी पहले कल्पना नहीं थी।

आतंकवाद के भय से सहमे रहने वाले दूरस्थ इलाकों तक भी विकास पहुंचा, स्थानीय निकायों के चुनाव से निचले स्तर पर विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी, शिक्षण संस्थान सुचारू रूप से चलने लगे, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद आदि सामान्य गतिविधियों की तरह हो गए जिनकी पिछले तीन दशक से कल्पना भी नहीं थी। यह सच है कि भाजपा ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्टिक डेवलपमेंट काउंसिल और 2021 में पंचों एवं सरपंच के चुनाव कराए। बावजूद कश्मीर में उसका खाता न खुलना चिंता का विषय होना चाहिए। किंतु इसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भाजपा जम्मू में 41 तथा कश्मीर में 19 सीटों यानी कुल 60 स्थानों पर चुनाव लड़ा। पार्टी ने पहली बार 23 मुस्लिम प्रत्याशी दिए। दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन में कांग्रेस 32 और नेकां 51 पर चुनाव लड़े और तथा 5 सीटों पर दोनों के बीच मुकाबला था। प्रदेश में पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सज्जाद लोन की पीपुल्स कांफ्रेंस, आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी आदि मैदान में थे। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी तो खैर थी ही। जम्मू क्षेत्र के बारे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वहां एक तिहाई आबादी

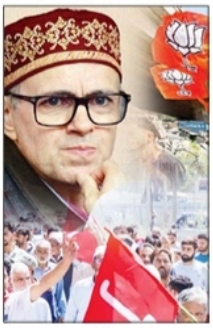

मुस्लिम है। केवल चार जिले जम्मू, कठुआ, सांभा और उधमपुर में हिंदू बहुमत में हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवादी, अलगाववादी हिंसा की अस्थिर स्थिति में लंबे समय से रहा। उसमें 370 हटाने के बाद परिस्थितियों को एकाएक सामान्य करना तथा प्रशासनिक व राजनीतिक-सामाजिक सांस्कृतिक-गतिविधियों से लोगों तक पहुंचकर उन्हें समझा पाना असंभव था। उतना बड़ा कदम, जो अकल्पनीय था तथा लंबे समय की यथास्थिति को एकाएक धक्का देकर प्रदेश को आमूल रूप से बदलने का कदम था।

भाजपा घाटी में कहीं थी नहीं और मुसलमानों के बीच उसे लेकर हमेशा गलतफहमी बनाई गई। भाजपा स्थापित की गई भारत की अखंडता सिद्धांत के विपरीत धारणा के विरुद्ध रही है। इस विचार की सहयात्री नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस वहां की स्थापित पार्टियां रही हैं। बाद में पीडीपी भी मुख्य पार्टी बन गई और इनका जनाधार दोनों क्षेत्रों में रहा है। उनको काट पाना आसान नहीं था। हालांकि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर से समाप्त पार्टी साबित हुई क्योंकि उसे 5 सीटें घाटी से मिली जिनके कारण नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन है और एक सीट केवल पीर पंजाल से। बाकी जम्मू में वह कहीं भी जनाधार साबित नहीं कर पाई। दरअसल, कांग्रेस का अपना हमेशा एक अलग जनाधार जम्मू और घाटी दोनों क्षेत्रों में रहा है जो इस चुनाव में लगभग खत्म है।

अगर नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन नहीं होता तो संभव था उसे सीटें नहीं आती। पीडीपी केवल 8.7 फीसद मत आने वाली पार्टी रह गई और उसके बाद एकमात्र एनपी है जिसे 1 प्रतिशत से अधिक मत मिले। अन्य सभी पार्टियों को इनसे कम मत मिला है। भाजपा का यह आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि यह चिंता का विषय है कि धारा 370 हटाने के बाद आम आदमी भी मीडिया में बोल रहे थे कि उन्हें शासन में भागीदारी का अवसर मिला, शैक्षिक-सांस्कृतिक-खेलकूद आदि गतिविधियां बढ़ी, विकास के जबरदस्त काम हुए, लेकिन ये भाजपा को मत देने के लिए तैयार नहीं थे। कश्मीर की मुस्लिम पहचान की विरोधी पार्टी की छवि के साथ पूरे देश में इस समय मुसलमानों की सामूहिक प्रवृत्ति भाजपा के विरुद्ध मतदान की है। इसी कारण सभी मतदाताओं ने लगभग रणनीतिक मतदान किया। विकल्प के रूप में नेशनल कांफ्रेंस ही मजबूत दिख रही थी। इसीलिए प्रभावी निर्दलीय और शेष दल वहां नकारे गए।

नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी पार्टियों ने अलगाववादी वायदे किए थे जिनमें धारा 370 की वापसी, 1954 के पहले की स्थिति की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उन सारे कानूनों को समाप्त करना जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को प्रभावित करते हैं, भूस्वामित्व संबंधी बदले कानूनों का अंत, पाकिस्तान के साथ बातचीत आदि शामिल थे। अब नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन रही है तो देखना होगा अपने वादों को लेकर वो कितना आगे बढ़ते हैं। बढ़ते भी हैं या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण ज्यादातर मामलों में उन्हें उपराज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसलिए आसानी से अलगाववादी कट्टर मजहबी एजेंडा या पाकिस्तान परस्त विषयों को शामिल करना कठिन होगा या कहें कि असंभव होगा। इसलिए उमर के नेतृत्व वाली सरकार के रीति-नीति व्यवहार तथा भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का स्पष्ट स्वरूप आने में थोड़ा समय लगेगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी पार्टियों ने अलगाववादी वायदे किए थे जिनमें धारा 370 की वापसी, 1954 के पहले की स्थिति की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उन सारे कानूनों को समाप्त करना जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को प्रभावित करते हैं, भूस्वामित्व संबंधी बदले कानूनों का अंत, पाकिस्तान के साथ बातचीत आदि शामिल थे। अब नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन रही है तो देखना होगा अपने वादों को लेकर वो कितना आगे बढ़ते हैं

बेतहाशा बारिश से बढ़ा मौत का जोखिम

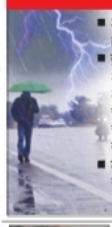

- अत्यधिक बारिश के मद्देनजर मौत का जोखिम बढ़ गया है, जिसमें हृदय और फेफड़ों की बीमारियों के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं
- दुनियाभर बारिश की 62 हजार से ज्यादा घटनाओं पर आधारित एक अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तेज और बार-बार होने वाली अल्पकालिक बारिश से ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि इन घटनाओं और स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल असर विशेष रूप से संक्रामक रोगों के प्रसार के बीच एक मजबूत संबंध का संकेत करते हैं
- जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ के शोधकर्ता इस अध्ययन में शामिल थे। यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

चुनाव की घोषणा की पूर्व संध्या पर, महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में प्रवेश करने वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल टैक्स माफी की घोषणा की है। बार-बार मांग के बावजूद 22 साल से टोल टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई थी। अब अचानक महाराष्ट्र सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

न उजाड़ें नैसर्गिक संरचनाओं को

जंगली जानवर

पंकज चतुर्वेदी

ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम में जंगल में मंगल होता है। घने वन झूमते हैं और हर जानवर के लिए पर्याप्त भोजन होता है, लेकिन इस बार अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में तेंदुए ऐसे मौसम में बस्ती की तरफ आ रहे हैं और उनकी भिड़ंत इंसान से हो रही है। मुरादाबाद- अमरोहा के सैकड़ों किसान तेंदुए के डर से खेत नहीं जा रहे तो लोगों ने दिन में भी जंगल या एकांत से गुजरना छोड़ दिया है। हापुड़ और मेरठ में भी घनी बस्ती में तेंदुआ पालतू जानवरों का शिकार कर चुका है। बिजनौर में तेंदुआ 25 से अधिक जान ले चुका है। पीलीभीत के आसपास एक हजार से अधिक तेंदुओं के घूमने की बात जंगल महकमा कह रहा है। उत्तर प्रदेश में तो भेड़िये, सियार, कुछ जगह गुलदार और बाघ के कारण लोगों में दहशत है, लेकिन असम, राजस्थान , हिमाचल प्रदेश से भी तेंदुए के गांवों तक आने की खबर को सामान्य नहीं माना जा सकता।

यह सच है कि जंगलों में बाघ की संख्या बढ़ने से तेंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन बरसात में पलायन का बड़ा कारण बदलता मौसम है। तेंदुए जैसे जानवर को क्या जलवायु अपरिवर्तन से जूझने में दिक्कत हो रही है? यह सच है कि जब जंगल का जानवर बस्ती में दिखता है तो इंसान में भी डर की भावना आती है। एक तो समझना होगा कि तेंदुआ बस्ती की तरफ या क्यों रहा है, दूसरा यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी जानवर इंसान पर हमला करने के लिए गांव-शहर में आता नहीं, फिर इस बात का ऐसा निदान खोजा जा सकता है कि प्रकृति की यह सुंदर देन अपने नैसर्गिक पर्यवास में निरापद रहे। चीता हमारे सामने उदाहरण है कि आजादी के बाद कैसे वह हमारे देश से लुप्त हुआ था। आज भले ही तेंदुए की संख्या पर्याप्त है, लेकिन जब उसका इंसान से टकराव बढ़ेगा तो जाहिर है कि उसके प्रजनन, भोजन, पर्यवास सभी पर कुप्रभाव पड़ेगा, खासकर जब जलवायु परिवर्तन की मार अब जानवरों पर बुरी तरह से पड़ रही है। यह बात गौर करने की है कि कुछ साल पहले तक तेंदुए के शावक जनवरी से मार्च तक दिखाई देते थे, लेकिन इस बार भारी बरसात में अर्थात जुलाई में जगह-जगह शावक दिख रहे हैं। जाहिर है कि बदलते मौसम ने तेंदुए के प्रजनन काल में बदलाव कर दिया है। हो यह रहा है कि बाघ के कारण तेंदुए जंगल छोड़ने पर

जब मजबूर होते हैं तो वे बस्ती-शहर के पास डेरा डालते हैं, जहां तापमान बढ़ने का कुप्रभाव सबसे अधिक है और इस ने उनक काई मूल स्वभाव में परिवर्तन ला दिया है। घने जंगल कम होने से तेंदुए के इलाके में बाघ का कब्जा हो गया और जब पानी और घास पर जीने वाले जीव, जोकि मांसाहारी जानवरों के भोजन होते हैं, उनकी पर्याप्त संख्या होने के बावजूद तेंदुए को अधिक गरम इलाके में आना पड़ रहा है। जान लें कि जंगल का जानवर इंसान से सर्वाधिक भयभीत रहता है और वह बस्ती में तभी घुसता है जब वह पानी या भोजन की तलाश में बेहाल हो जाए। चूंकि तेंदुआ कुत्ते से लेकर मुर्गी तक को खा सकता है अतः जब एक बार लोगों की बस्ती की राह पकड़ लेता है तो सहजता से शिकार मिलने के लोभ में बार-बार यहां आता है। घने जंगल में बिल्ली मौसी के परिवार के बड़े सदस्य बाघ का कब्जा होता है और इसीलिए परिवार के छोटे सदस्य जैसे तेंदुए या गुलदार बस्ती की तरफ भागते हैं। विडंबना है कि जंगल के संरक्षक जानवर हों या फिर खेती-किसानी के सहयोगी मवेशी, उनके के लिए पानी या भोजन की कोई दूरगामी नीति नहीं है। तेंदुआ एक अच्छा शिकारी तो है ही, किसी इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता का मानक चिह्न भी होता है। दुर्भाग्य है कि आज इसका अस्तित्व ही खतरे में है। जंगली बिल्लियों के कुनबे के मूलभूत गुणों से विपरीत इनका स्वभाव हालात के अनुसार खुद को ढाल लेने का होता है। जैसे कि ये चूहों और साही से लेकर बंदरों और कुत्तों तक किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। वे गहरे जंगलों और मानव बस्तियों के पास पनप सकते हैं। यह अनुकूलन क्षमता, इन्हें कहीं भी छिपने और इंसान के साथ जीने के काबिल बना देती है, लेकिन जब तेंदुए जंगलों के बाहर उच्च मानव घनत्व वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो हमें लगता है कि वे भटक गए हैं।

हम भूल जाते हैं कि यह उनका भी घर है, उतना ही हमारा भी है। तेंदुआ अपना जंगल छोड़ कर यदि लंबी यात्रा करता है तो उसका कारण भोजन के अलावा अपनी यौन क्रिया के लिए साथी तलाशना होता है। तेंदुए को यदि एक बार इंसान के खून की लत लग जाए तो यह खतरनाक होता है। जंगल का अपने एक चक्र हुआ करता था। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और उसमें बसने वाले जानवरों के प्राकृतिक पर्यवास के नष्ट होने से इंसानी दखल से दूर रहने वाले जानवर सीधे मानव के संपर्क में आ गए। यदि इंसान चाहता है कि वह तेंदुए जैसे जंगली जानवरों का निवाला ना बने तो जरूरत है कि नैसर्गिक जंगलों को छेड़ा ना जाए, जंगल में इंसानों की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगे। खासकर जंगलों में नदी-नालों को खनिज या रेत उत्सर्जन के नाम पर नैसर्गिक संरचनाओं को उजाड़ा न जाए।

एक में ठहरो

ओशो

मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था तो उसने अपने बेटे को कहा कि अब मैं तुझे दो बातें समझा देता हूं। मरने के पहले ही तुझे कह जाता हूं इन्हें ध्यान में रखना। दो बातें है। एक आनेस्टी (ईमानदारी) और दूसरी है-विजडम (बुद्धिमानी)। तो, दुकान तू सम्हालेगा, काम तू सम्हालेगा। दुकान पर तख्ती लगी है आनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। (ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।) इसका तू पालन करना। कभी किसी को धोखा मत देना। कभी वचन भंग मत करना। बेटे ने कहा, 'ठीक, दूसरा क्या है? बुद्धिमानी, उसका क्या अर्थ है?' नसरुद्दीन ने कहा, 'भूलकर कभी किसी को वचन मत देना।' बस, ऐसा ही विपरीत बंटा हुआ जीवन है। ईमानदारी भी और बुद्धिमानी भी, दोनों संभालने की कोशिश है। वचन पूरा करना ईमानदारी का लक्ष्य है। वचन कभी न देना बुद्धिमानी का लक्ष्य है। इधर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजें और उधर तुम चाहते हो कि तुम पापी की तरह मजे भी लूटो। बड़ी कठिनाई है। इधर तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम्हारे चरित्र का गुणगान हो; लेकिन उधर तुम रावण की तरह दूसरे की सीता को भगाने में तत्पर हो। तुम असंभव संभव करना चाहते हो। तुम होना तो रावण जैसा चाहते हो; प्रतिष्ठा राम जैसी चाहते हो। बस, तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तब विपरीत दिशाओं में तुम्हारी यात्रा चलती है और अनंत तुम लक्ष्य बना लेते हो। उन सब में तुम बंट जाते हो। टुकड़े-टुकड़े हो जाते हो। जीवन के आखिर में तुम पाओगे जो भी तुम लेकर आए थे, वह खो गया। एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ। बहुत समझाया पत्नी ने, परिवार ने, मित्रों ने; लेकिन उसने सुना नहीं। एक दिन ऐसी हालत आ गई कि सिर्फ एक रुपया घर में बचा। पत्नी ने कहा, 'अब तो चौंको।' पति ने कहा, 'जब इतना सब चला गया है और एक रुपया ही बचा है तो आखिरी मौका मुझे और दे। कौन जाने, एक रुपये से भाग्य खुल जाए।' जुआरी गया जुए के अड्डे पर। बड़ा चकित हुआ। हर बाजी जीतने लगा। अंत में उसने लाख भी लगा दिए और कहा कि बस, अब आखिरी हल हो गया सब। और वह सब हार गया। वह घर लौटा। पत्नी ने पूछा, 'क्या हुआ?' उसने कहा कि एक रुपया भी चल गया। मरते वक्त तुम पाओगे कि जो आत्मा तुम लेकर आए थे, वह तुम गंवाकर जा रहे हो। बस, एक खो जाएगा! बाकी तुमने जो गंवाया, जोड़ा, मिटाया, बनाया, उसका कोई बड़ा हिसाब नहीं है।

रीडर्स मेल

सरकार बदले अपना रवैया

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अथक प्रयास के बावजूद सीवर में सफाई कर्मचारियों की मौत गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस समस्या का हाल-फिलहाल कोई समाधान दिखाई नहीं देता है। राजधानी दिल्ली के बीआईपी इलाके सरोजनी नगर इलाके में दो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु ने सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। एक अनुमान के अनुसार करीब 2 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी दिल्ली सरकार और निजी संस्थाओं में काम करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में सीवर में करीब 70 मौत हर वर्ष दर्ज की जाती है। इन सफाई कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मुआवजा राशि भी आसानी से नहीं प्राप्त होती है। ठेकेदारों के द्वारा इन सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचना होगा कि सफाई कर्मचारी को सीवर में उतरने की जरूरत ही ना पड़े। यदि मानवीय पहलू को देखा जाए तो यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि गरीब सफाई कर्मचारियों को मजबूर किया जाता है कि वह जान की बाजी लगाकर गटर में उतरें और सफाई करें। देशभर की गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं के द्वारा इस पर लगातार काम किया जा रहा है कि इसे कैसे मुक्ति पाई जाए, लेकिन अभी तक हालात बदले नहीं हैं। 21वीं सदी के बाद भी हमारे यहां सीवर में जाने वाले सफाई मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोई उपकरण नहीं बनाए गए हैं। अगर उपकरण हैं भी तो उसे इन मजदूरों को नहीं मुहैया कराया जाता है। लाजिमी है कि सरकार अपना रवैया बदले।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

तीर्थ स्थल सुधार लाएं

नवरात्रि के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री वैष्णो देवी की यात्रा पर गए, लाखों लोगों में से मैं भी एक था। वहां जाने के पश्चात प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक कोई दुकान नहीं था जहां डिजिटल पेमेंट हो सके, कुछ खरीदने के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। वहां नेटवर्क की भी समस्या नहीं थी। अब सोचने वाली बात और जांच का विषय ये है कि जहां हमारी सरकार डिजिटल पेमेंट को इतना बढ़ावा दे रही है। वहीं इतने बड़े तीर्थस्थल में क्यों डिजिटल पेमेंट स्वीकार्य नहीं किया जा रहा।

सूरज कुमार, आईआईएमसी, जम्मू

सरकारी संरक्षण और गुंडे

इसी को इको सिस्टम कहते हैं, जब कोई कुख्यात नेता बनता है तो कोई हाय-तौबा नहीं होती, लेकिन अपनी करतूतों के लिए अगर वो मारा जाता है तो वो एकदम महान हो जाता है। लॉरेंस विश्नोई पर हाय-तौबा खूब मचाया जा रहा है, क्योंकि मरने वाला एक मुसलमान बाबा सिद्दीकी था, अगर यही विश्नोई किसी हिंदू सनातनी को मारा होता तो मुर्दानी खामोशी ओढ़ ली जाती, हर तरफ से आवाज तेज होने लगती। इसलिए अपने समाज की रक्षा के के प्रति समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है। कोई भी बदमाश बिना सरकारी मदद या संरक्षण के बड़ा माफिया या अंडर वर्ल्ड डॉन नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बात लाखों वर्षों के अर्जित ज्ञान के बाद लिखी गई है। नेता और सरकारें माफिया या डॉन को जन्म देती है और उसका पालन-पोषण भी करती है। लॉरेंस विश्नोई भी सरकारी प्रॉडक्ट है।

अभिषेक तिवारी, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 61
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के वचन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

दैनिक जागरण
अशांति उन्नति में सबसे बड़ा अवरोध बनती है

अस्तित्व के संकट से जूझते वाम दल

शंकर शरण

आज कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति उस पुराने कारखाने जैसी है, जिसका बड़ा कार्यालय और गोदाम तो है, किंतु उसमें उत्पादन बंदहै

अपलेट तरापुरा

सीताराम येचुरी के निधन के बाद प्रकाश करात ने माकपा की अंतरिम कमान संभाल ली। यह खबर बहुत चर्चा का विषय नहीं बनी। करात इस भूमिका के लिए नए भी नहीं हैं। येचुरी से पहले 2005 से 2015 तक वही माकपा महासचिव रहे। उनके नेतृत्व में ही माकपा का अभूतपूर्व ह्रास हुआ। इसलिए पुनः उन्हीं की कमान मिलना यही संकेत है कि पार्टी में नए नेताओं का अभाव हो चुका है। वामपंथी हलकों में यह जानी-मानी बात है कि करात के सख्त रुख के कारण ही माकपा ने कांग्रेस से नाता तोड़ा और उसके बाद से पार्टी निरंतर हाशिये पर जा रही है। अभी लोकसभा में माकपा की चार और भाकपा की दो सीटें हैं। बंगाल-त्रिपुरा जैसे पार्टी के दुर्ग ध्वस्त हो गए। केरल ही अंतिम ठिकाना बचा हुआ है।

कम्युनिस्टों के ऐसे पराभव का एक कारण अपनी महत्ता का अतिरेकित मूल्यांकन करना भी था। एक समय कम्युनिस्ट पार्टियां देश में विशिष्ट स्थान रखती थीं। पचास साल पहले के अखबार उलटकर देखें जब जेपी आंदोलन चल रहा था, तब भाकपा कांग्रेस सरकार के साथ थी। जेपी के सांप्तातिक 'एवरीमैंस' के हर अंक में कांग्रेस के साथ भाकपा पर भी चोट होती थी। दूसरी ओर, माकपा को साथे रखने के लिए जेपी खुद को 'माओ का शिष्य' बताते हुए 'एक क्रांतिकारी ही दूसरे को पहचान सकता है' जैसी बातें करते थे। इसका अर्थ था कि देश के दोनों बड़े राजनीतिक धड़ों यानी पक्ष और विपक्ष पर कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव था। इसके पीछे तब विश्व राजनीति में सोवियत कम्युनिज्म की सशक्त उपस्थिति भी थी। यह परिस्थितियों का परिणाम भी था, क्योंकि तब विश्व में सोवियत संघ तथा भारत में कांग्रेस-सत्ता संरक्षण में यही वामपंथी शक्तिशाली थे। केवल अपने बूते वह कभी भी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं बढ़ सके। भाकपा ने कांग्रेस के साथ और माकपा ने गैर-कांग्रेसी दलों के साथ तालमेल रखकर ही अपनी ताकत बढ़ाई।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचार आम जनगण को कभी न छू सके। इस विचार का प्रभाव मुख्यतः बुद्धिजीवियों के बीच रहा और अक्सरीय रूप में आज भी है। जबकि कम्युनिस्टों की संसदीय और सत्ता-स्थिति अपने संगठन के साथ-साथ बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ मोर्चेबंदी पर ही निर्भर रही। कट्टर कम्युनिस्ट इस सच्चाई से मुंह फेरते हैं। अपने मतवाद पर अंधविश्वास से वे तुनिया में कम्युनिज्म का आना अवश्यंभावी मानते थे, बिल्कुल वैसे जैसे इस्लामी कट्टरपंथी पूरी दुनिया का इस्लामी बनना अल्लाह की लकीर मानते हैं। इसीलिए, कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस आदि दलों की पतनशील मान रखा था, जिन्हें आज न कल कम्युनिस्टों के अनुसर चलना होगा। पुराने कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे को बहुत पहले ही यह अनुभूति हो गई थी कि किसी बड़े उदारवादी दल की छत्रछाया के बिना कम्युनिस्ट खस्ताहाल रहेंगे। जनसंघ को हराने के लिए भी वह कांग्रेस से सहयोग जरूरी मानते थे। दोनों का इकट्ठा विरोध करके कम्युनिस्ट प्रभावी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए डांगे ने कांग्रेस के साथ मोर्चा बनाए रखना जरूरी समझा था। हालांकि, 1977 में कांग्रेस की हार के बाद भाकपा नेताओं ने न केवल कांग्रेस से संबंध तोड़ा, बल्कि डांगे को पार्टी से भी निकाल दिया। यह कैसी विडंबना है कि आज दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां उसी रीति-नीति पर आ लौटी हैं जिसकी डांगे ने वकालत की थी। येचुरी ने उसी नीति को अपनाकर माकपा को बचाने का प्रयास किया।

कुछ कम्युनिस्ट अभी भी 'कारपोरेट के विरुद्ध जन-आंदोलन' चलाने की बात करते हैं। वे अपने इतिहास की समीक्षा के बदले अमेरिका और कारपोरेट जगत की स्थायी निंदा ही पवित्र 'आइडियोलजी' समझते हैं। इसमें सोवियत रूस और लाल चीन के दशकों के प्रतिकूल अनुभव भी नजरंदाज करते हैं। यद रहे कि जीवन हानि-लाभ के ठोस गणित से चलता है, किसी आइडियोलाजी से नहीं। इसीलिए बंगाल और पूरे देश में असंख्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने भी दूसरी पार्टियों का दामन पकड़ लिया, जिनमें कई दिग्गज भी रहे। असल में यही हिसाब तब भी था, जब कम्युनिस्ट पार्टियां अन्य दलों के साथ सहयोग से अपनी ताकत बढ़ाती थीं। उसे केवल अपने सिद्धांत, संघर्ष और संगठन का बल समझना एक भ्रम था। निःसंदेह एक पुरानी पार्टी और विशिष्ट विचारों के कारण उनकी एक पहचान थी। वह पहचान आज भी है, उसे फौरन खो देना आसान नहीं। यह स्थिति अधिक समय तक रहनी कठिन है। वे या तो समाज में कोई खाली जगह ले सकते हैं अथवा खत्म हो जाएंगे। वह जगह पाने के लिए उन्हें झूठी मान्यताएं छोड़नी होंगी। अंध-कारपोरेट विरोध, अंध-अमेरिका विरोध में उन्होंने यह अनहेखा किया कि यहां बड़े उद्योगों और अमेरिकी नीतियों-कंपनियों ने ही सबसे बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया। सभी युवा उसके लिए उत्सुक रहते हैं। जबकि अपनी जड़ मान्यताओं के भरोसे कम्युनिस्टों ने उग्र नारेबाजी, बंद, हड़ताल और हिंसा आदि के 'वर्ग-युद्ध' चलाकर बंगाल जैसे उन्नत प्रदेश को खंडहर बना दिया। नई अमेरिकी तकनीकी, आविष्कारों और कंपनियों ने ही दुनिया भर में सधारण मजदूरों तक के सुविधाएं घर-घर पहुंचा दीं, जो चार दशक पहले मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी सपने सरीखी थीं। लोगों ने खुद ही देख लिया कि कौन से विचार ने गरीब लोगों का अधिक भला किया और जीवन को सुगम बनाया, लेकिन कम्युनिस्टों ने कभी खेद समीक्षा नहीं की। उलटे वह हर तकनीक और नवाचार का विरोध करते रहे। यह झूठी समझ थी। जबकि चार दशक पहले चीनी नेता देंग ने उन झूठी मान्यताओं को तिलांजलि देकर अमेरिकी सहयोग से ही चीन को फिर पटरी पर खड़ा किया, जो माओ के कट्टर कम्युनिज्म में संभव रूप से तबाह हो चुका था। इस वास्तविकता से सैंकड़ कर भारतीय कम्युनिस्ट दल भी कुछ सबक कर सकते हैं। आज हरेक दल तुरंत लाभ मिलने वाले मुद्दों पर लगा है। नैतिक प्रश्नों को उठाने की जगह खाली है। चाहे तो आमपंथी अपनी मतबादी निष्ठा छोड़ सत्यनिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। यही नैतिक प्रजनीति होगी। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यपक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कनाडा की करतूत

भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला कर बिल्कुल सही कदम उठाया। कनाडा सरकार को भारत विरोधी गतिविधियां जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं और अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए वह जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है, उसका करारा जबाब देना आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा, क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों को कथित लिप्तता की जांच करने की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहां पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए बीजा सेब रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ब्व निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इन्कार कर रही है। ब्व इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कनाडा पहुंचा था। उसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया था, लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी थी।

खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वह खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि ब्व भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारत की आपत्तियों के बाद भी ब्व ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी अतिवादियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या को परेड निकालते हैं और उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं और यहां तक कि उनके पोस्टरों पर गोलीबारी करते हुए बैडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का जो फैसला किया, उससे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन सरकार और अधिक खुलकर खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि ब्व कनाडा पर और अधिक दबाब कैसे बनाए?

भूमि सर्वेक्षण की बाधाएं

बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बाधा म्युटेशन भी है। इसको लेकर अफरातफरी मची है। गौरतलब यह कि सितंबर में किसी भी जिले के जिलाधिकारी ने इससे संबंधित एक भी मामला कोर्ट में नहीं देखा। डीएम की कोर्ट में जाने के पूर्व म्युटेशन का मामला कई स्तरों से गुजरता है। आवेदक सर्वप्रथम सीओ के यहां आवेदन करता है। यह मामला डीसीएलआर के यहां से होते हुए एडीएम तक पहुंचता है। यदि आवेदक इन स्तरों के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो यह मामला डीएम की कोर्ट में पहुंचता है। सितंबर की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के सभी 38 जिलों के किसी भी डीएम ने अपनी कोर्ट में इस मामले को नहीं देखा। जाहिर है, इसका असर भूमि सर्वेक्षण पर भी पड़ रहा है। डीएम म्युटेशन के कार्यों की प्रगति के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्हें सीओ से लेकर एडीएम स्तर तक इस संबंध में हो रहे कार्यों पर निगरानी रखनी है। आवश्यक दिशा-निर्देश भी देने हैं। पर्यवेक्षण के मामले में भी कई जिले पिछड़े दिखते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार म्युटेशन के पर्यवेक्षण में बांका जिला सबसे आगे है। औरंगाबाद की स्थिति कमजोर है। हालांकि जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों के निष्पादन में औरंगाबाद टाप पांच जिलों में है। पटना जिले की स्थिति दोनों ही मामले में संतोषजनक नहीं है। जाहिर है, जो जिले जमीन से जुड़े कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण में पिछड़ रहे वहां के जिलाधिकारियों को रणनीति बनाकर कदम करना होगा, ताकि जिलों की रैंकिंग में सुधार हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब जिलों की रैंकिंग के अंकों को डीएम के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में हर हाल में सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों की रैंकिंग सुधारनी होगी। तेज गति से कदम करना होगा। इससे विशेष भूमि सर्वेक्षण को भी गति मिलेगी।

हरियाणा ने दिखाया कांग्रेस को आईना

अभिनव प्रकाश

जहां कांग्रेस '36 बिरादरी' की केवल बात करती रही, वहीं भाजपा ने साझा एजेंडे के तहत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया

भाजपा को मिला सभी वर्गों का साथ। प्रेट

हरियाणा विधानसभा चुनाव का जनादेश ऐतिहासिक है। पहली बार हरियाणा में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हरियाणा की राजनीति मजबूत क्षेत्रीय नेताओं, परिवारवाद और अस्थिरता के कारण जानी जाती रही है। राजनीति का प्रसिद्ध मुहावरा 'आया राम, गया राम' हरियाणा से ही निकला। ऐसे में सभी एक्जिट पोल को नकारता हरियाणा का परिणाम राज्य में मूलभूत परिवर्तन की दर्शाता है। यह जनादेश हरियाणा की जनता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। हरियाणा से तीन ओर से घिरे होने के कारण कांग्रेस की जीत दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती थी। राहुल गांधी के अराजकतावादी एजेंडे के अंतर्गत दिल्ली को बार-बार आंदोलनों और धरना-प्रदर्शन के नाम पर बंद किया जाता। इससे मोदी सरकार का कामकाज और भारत की विकास यात्रा बाधित होती, लेकिन कांग्रेस यह भूल गई कि हरियाणा में राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और आम जनता राहुल गांधी के वामपंथी और अराजक एजेंडे को नहीं स्वीकारती।

हरियाणा की जनता ने आंदोलनों के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करने वाली राजनीति को नकारा है। खरखौंद पर दिल्ली बार्डर से लगने वाले इलाकों में कांग्रेस की भारी हार हुई है। हरियाणा का नतीजा पिछले दस वर्षों की भाजपा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर मुहर है। 2014 में भाजपा हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति में एक बदलाव के तौर पर आई। यहां पहले जाति और परिवार आधारित सरपरस्ती हावी रहती थी और कानून का शासन दूसरे पायदान पर रहता था। यह सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में खत्तलीन पर दिखता था, जहां भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद हावी थे। भाजपा सरकार के तहत चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हुई और सरकारी नौकरियों में दे लाख से अधिक लोगों का चयन हुआ। हर जाति और क्षेत्र को इस नई प्रणाली का लाभ मिला। 'बिना खर्ची और पर्ची' की यह व्यवस्था युवाओं के बीच भाजपा के प्रति अडिग विश्वास का कारण बनी।

नयब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने का फैसला भी जीत का एक महत्वपूर्ण कारक है। सैनी पार्टी में नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं और बहुत कम जनसंख्या वाले अति-पिछड़ा वर्ग से हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता में यह संदेश गया कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि से हो, शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है। यह जीत भाजपा संगठन की भी जीत है। हालिया लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस की आक्रामकता के बावजूद भाजपा संगठन ने मजबूती से अपनी जमीन बनाए रखी। कांग्रेस द्वारा जमीन पर दी जा रही धामकियों और प्रलोभन के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता मजबूती से डटे रहे। उन्होंने घर-घर प्रचार किया, ड्राइंग रूम बैठकों का आयोजन किया, बाइक रैलियों का नेतृत्व किया। उन इलाकों में भी पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार के सब्ब खड़े रहे, जहां जीत असंभव प्रतीत हो रही थी।

भाजपा असाधारण काम करने वाले साधारण लोगों की पार्टी है, जिनके सामने कांग्रेस का सरा धन-बल और बाहुबल हार गया। अगस्त माह में नयब सिंह सैनी और तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति में 30 सल से कम आयु के एक हजार युवा और जुड़ी यह बेहतरी महिलाओं के जीवन में भी सुधार लाने वाली है। बहुत से मोर्चों पर आ रहे सकारात्मक बदलावों के बीच आवश्यक है तो यह कि निरत कर्मशील रहने वाली ग्रामीण स्त्रियें की भूमिका को मन से मान भी दिया जाए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मुख्य आधार-स्तंभ माना जाता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस द्वारा धन-बल के आधार पर बनाए जा रहे माहौल के बिपरीत हरियाणा का युवा भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा रहा। प्रचार के दौरान यह भी भी स्पष्ट दिखने लगा कि युवा वर्ग जाति की सीमाओं से परे भाजपा का समर्थन कर रहा है, जो नए भारत की उम्मीद और महत्वकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।

भाजपा का प्रचार और एजेंडा सर्वसमावेशी था। जहां कांग्रेस 'जातियों के आधार' पर अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं भाजपा ने 'गरीब' को ही एकमात्र जाति माना। इसके तहत समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के बीच गहरी पैठ बना चुकी है, जो आज भी कांग्रेस शासन में व्याप्त सामाजिक दमन, हिंसा और सरकार का रवैया भूले नहीं हैं। भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहली बार इन वर्गों तक पहुंचीं। उन्हें गर्व-समाज के दबंग तबकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, जिससे दस वर्षों में राजनीतिक 'बंधुआ मजदूरी' भी समाप्त हुई। भाजपा सरकार की योजनाओं ने न केवल किसनों को, बल्कि सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी लाभान्वित किया, जिनके हितों को पूर्ववर्ती सरकारों में सदैव नजरअंदाज किया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान इन वर्गों के लोग गांव की बैठकों और सभाओं में चुचप्पाप आते तथा घर-घर प्रचार के दौरान बिना कुछ बोले सुनते। अंततः चोट के माध्यम से ही इन वर्गों की आवाज सुनाई दी। हरियाणी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे मुखर समर्थक बनकर उभरी हैं। पिछले चुनावों की तरह ही इस बार भी शहरी मतदाता और शिक्षित युवा भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। इन सब कारणों से भाजपा हरियाणा में एक उम्मीद और प्रगति की पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस को दिन-प्रतिदिन एक निराशावादी और अराजक पार्टी के रूप में देखा जाने लगा। जहां कांग्रेस '36 बिरादरी' की केवल बात करती रही, वहीं भाजपा ने सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया और एक सझा एजेंडे के आधार पर सर्वमान्य पार्टी बनकर उभरी। यह व्यापक समावेशिता ही भाजपा की चुनावी अपील का एक प्रमुख स्तंभ बन गई, जिसने पार्टी को इस ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(लेखक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्षमाशीलता

क्षमाशीलता एक ऐसा गुण है जिसे अपने आवेश पर नियंत्रण रखते हुए और अपमान सहन करने की प्रवृत्ति के साथ शनैः शनैः विकसित किया जा सकता है। यह गुण द्विआयामी होता है? अर्थात किसी की गलती पर उसे क्षमा कर देना और अपनी गलती पर उसे क्षमा मांग लेना इसकी सार्थकता होती है। अपने आवेश और अपमान पर पूर्ण नियंत्रण कर सकने वाला व्यक्ति ही क्षमाशील हो सकता है। मानव के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उसे प्रोधित अथवा अपमानित होना पड़ता है। इन विषम अवस्थों पर वह प्रतिकार स्वरूप प्रोधित होने या अपने अपमान का बदला लेने की तत्परता दिखाता है, किंतु इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति सौम्य मुस्कुराहट के साथ अपने स्वभाव की उदारता को दिखाता है तो निःसंदेह इससे उसके क्षमाशील होने का ही परिचय मिलेगा।

धर्मग्रंथों में बताया गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति क्षमा करे तो यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होगा। किसी कमजोर-दुर्बल व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली क्षमा अर्थहीन कही जाएगी। एक बार क्रोधातुर भृगु ऋषि ने श्रीहरि विष्णु जी की छाती पर पाद प्रहार किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके पैरों को सहलाते हुए कहा कि 'ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं आई?' रहीम ने इस पर कहा कि 'छमा बड़न को चाहिये, छोटन को उतपात। कह रहीम हरि का घटयौ, जो भृगु मारी लात।' यानी क्षमा बड़प्पन का स्वभाव है और उत्पात छोटे और ओछे लोगों की प्रवृत्ति। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के साथ जो किया, विष्णु जी ने इस कृत्य पर भृगु को क्षमा कर दिया। इससे विष्णु का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। इसीलिए हमारे धर्म में क्षमादान को ही श्रेष्ठ दान माना गया है। हम इस क्षमाशीलता रूपी पुष्प से अपने स्वभाव रूपी मधुबन को महका सकें, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

एसएन दुबे 'स्नेही'

ग्रामीण महिलाओं को भी मिले मान

डा. मोनिका शर्मा

श्रमशक्ति में भागीदारी हो या सामाजिक जीवन को सहेजने का भाव, ग्रामीण महिलाओं की भूमिका सदा से अहम रही है

हमारे कृषि प्रधान देश में महिला कृषकों का अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित संकल्पों की सूची में शामिल अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस से जुड़ा संदेश बहुत मायने भी रखता है। हर साल 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस विशेष दिन के उद्देश्यों की सूची में कृषि और ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी मिटाने के प्रयासों की बात देश-दुनिया में शामिल है। समग्र समाज और देश की बेहतरी से जुड़ी इन कोशिशों में ग्रामीण महिलाओं की रेखांकित करने योग्य भूमिका और योगदान को मान्यता देने का संकल्प भी लिए है।

अधिकतर खेती-किसानी से जुड़ी ग्रामीण स्त्रियों की भूमिका को भोजन प्रदाता और पर्यावरण रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। हमारे यहां तो महिला किसान्नें को अन्नपूर्णा ही कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की 60 से 80 प्रतिशत तक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। बीज लगाने और निराई-गुड़ाई करने से लेकर कटाई तक खेती किसानी से जुड़े 73 प्रतिशत काम महिला किसान ही करती हैं। खेती-किसनें के काम करने के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो उनके हिस्से है ही। बावजूद इसके इन श्रमशील महिलाओं की भागीदारी की बात कम ही होती है। ज्ञात हो कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 2024 का विषय भी 'ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छा भोजन उगा रही हैं' है। यह विषय स्पष्ट रूप से समझाता है कि ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार में ही नहीं, समग्र समुदाय में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। कृषि और ग्रामीण उद्यमों में उनका योगदान न केवल देश, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को भी बल देता है। चिंतनीय है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं अपना स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखने के लिए समान रूप से पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता।

सुखद है कि हालिया वर्षों में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तीकरण से जुड़े प्रयासों से बड़ा बदलाव आया है। ऋण लेकर रोजगार शुरू करने से लेकर संस्थागत प्रसव के आंकड़े बढ़ने तक। ग्रामीण स्त्रियें सेहत और आर्थिक रूप से सशक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ताजा सर्वेक्षण में सामने आया है कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय पिछले पांच वर्षों में लगभग 58 प्रतिशत बढ़ी है। निःसंदेह पारिवारिक स्थितियों से जुड़ी यह बेहतरी महिलाओं के जीवन में भी सुधार लाने वाली है। बहुत से मोर्चों पर आ रहे सकारात्मक बदलावों के बीच आवश्यक है तो यह कि निरत कर्मशील रहने वाली ग्रामीण स्त्रियें की भूमिका को मन से मान भी दिया जाए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मुश्किल में विपक्ष

'हरियाणा ने बदला राजनीतिक माहौल' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने हरियाणा चुनाव का विश्लेषण करते हुए यह ठीक ही कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जो खोया था वह हरियाणा की अप्रत्याशित जीत से हासिल कर लिया। भाजपा को पूर्ण बहुमत के स्थ तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने वाले हरियाणा के चुनावी परिणाम यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि कांग्रेस ने किसान, पहलवान और अग्निवीर को लेकर जो झूठे नैरेटिव गढ़े थे उन्हें हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। कहते हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहित आइएनडीआइए के अन्य नेताओं ने सत्ता पक्ष के विरुद्ध संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे नितांत झूठे नैरेटिव से भारतीय जनमानस को भ्रमित करके भाजपा को उसके लक्ष्य से पीछे जरूर धकेल दिया, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता इनके झांसे में नहीं आई। देश के आम जनमानस की अब विकास के प्रति जागरूकता बढ़ी है। निःसंदेह जिन राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार है उन राज्यों की कानून व्यवस्था और विकास की गति गैर-भाजपा शासित राज्यों से कहीं बेहतर है। जिन राज्यों में भाजपा का शासन है वहां पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती, लोकहितैषी विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और बेहतर कानून व्यवस्था ने देश की जनता को आकर्षित किया है। हरियाणा में भी जनभानस के इसी आकर्षण ने तीसरी बार फिर से कमल खिला दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के आगमी विधानसभा चुनाव में भी यदि जनभानस का यही विकासवादी सोच रहा तो यह झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले विपक्ष को मुश्किलों का बढ़ा देगा।

pandeywp1960@gmail.com

पंथनिरपेक्षता की गलत समझ

'खतरे में बांग्लादेशी हिंदू' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में भीजूद अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस को कठघरे में खड़ा किया गया है। यह अौचित्यपूर्ण प्रतीत हो रहा है। दरअसल अंतिम सरकार से कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने की जो उम्मीद की जा रही थी, इसके उलट उन्होंने पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया। ऐसे तत्व जेलों से रिहा किए जाने लगे, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि अनवरत वहां के हिंदुओं पर उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूजा पंडालों में उधम मचाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भीजूद सरकार और हिंदू संगठनों द्वारा वहां के हालात पर व्यक्त आपत्ति पर भी एतराज जता रहे हैं। आखिर ऐसे दल धार्मिक आजादी के अलंबरदार कैसे कहे जा सकते हैं? इस आजादी को प्रत्येक नागरिक के संदर्भ में कब देखेंगे?

मुकेश मनन, पटना

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत

'आकार लेती स्वास्थ्य क्रांति' शीर्षक आलेख के तहत विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा ने मोदी सरकार की उन नीतियों का विश्लेषण किया है जो देश को स्वास्थ्य बनाने के लिए ला रही है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी योजना है आयुष्मान योजना। अब सरकार ने 70 साल के हर वर्ग के बुजुर्ग को इस योजना के तहत लाने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार गरीबों को भी मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही है। यह कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान भी चला रही है। ये आयुष्मान कार्ड 2011 के जनगणना डाटा पर आधारित बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत से गरीब नहीं आ रहे, क्योंकि शायद उनका डाटा सरकारी तंत्र में अपडेट नहीं है। ऐसे गरीब लोगों का न तो राशन और न ही दूसरा ऐसे कोई कार्ड है जिसके जरिये वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकें। ऐसे गरीब लोगों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

इस साहा में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण साहा आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नरेन्द्र मोहन कला-संस्कृति एवं शिक्षा न्यास की ओर से संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक- विनोद गुप्त, प्रकाशन संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीलम ऑफसेट्स द्वारा प्लाट संख्या 501, आई.एस.एस. प्रिंटिंग एरिया, फेज-1, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-65, नोएडा में मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) : विष्णु प्रकाश त्रिपाठी *
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के पठन एवं संकलन हेतु पी. आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उलटराधे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। साप्ताहिक अवकाश ₹2 अतिरिक्त।

****

ख. मदन मोहन गुप्त
रिसर्च फेलो, सेंटर फार रीजियन एंड सेटल पीसिंग स्टडीज, जेएनयू

शंघाई सहयोग संगठन

वर्तमान बैठक से भारत की अपेक्षाएं

क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से शंघाई सहयोग संगठन एशिया का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संगठन है। मूल रूप से शंघाई-5 के नाम से स्थापित इस संगठन का विस्तार पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य एशियाई देशों से लेकर यूरोप तक है, जो यूरेशिया के 60 प्रतिशत क्षेत्र को शामिल करता है। इससे इस संगठन की आर्थिक, कूटनीतिक और भू-राजनीतिक महत्ता और प्रासंगिकता स्वत: बढ़ जाती है। मंगलवार और बुधवार को पाकिस्तान में आयोजित हो रही यह बैठक भारत के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक आयोजन स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मी। एपएपी

आज से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह एशिया का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संगठन है। वर्ष 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन की तुलना अमेरिकी-पश्चिमी देशों के सैनिक संगठन 'नाटो' से की जाती है। असल में शंघाई सहयोग संगठन में भारत, रूस और चीन की सदस्यता, यूरेशियाई सहयोग और आर्थिक प्रगति को परिलक्षित करता है। ऐसे में इस्लामाबाद में होने वाली शासनाध्यक्षों की बैठक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। शासनाध्यक्षों की इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर हिस्सा बनेंगे, जो भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि की पिछले नौ वर्षों में पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी।

इस बैठक को लेकर जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा और हस्ताक्षर होना है। इस बैठक में भारत निश्चित ही 'जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा' और 'हरित ऊर्जा' को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे पारिस्थितिकी संरक्षण में सदस्य देशों के बीच सहयोग स्थापित हो और भारत की 'इं-20' पहल को बढ़ावा मिल सके। ध्यान दें कि 'इं-20' पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित ईंधन का प्रयोग करना है। पूरी संभावना है कि विदेश मंत्री जयशंकर हरित ऊर्जा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर जोर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एशिया में पर्यावरण दोहन हो रहा है, भविष्य और अधिक कठिन होगा। आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन चीन कर रहा है, लेकिन नुकसान भुगान जैसे पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रों को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चाहे मध्य एशिया के देश हों या दक्षिण एशिया के, सभी देश चीन की आर्थिक नीतियों का शिकार हैं।

दूसरे, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना का मुख्य ध्येय आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद की समाप्ति है। शंघाई सहयोग संगठन वैश्विक आबादी में 40 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। चीन, रूस, भारत और अन्य सभी सदस्य देश अपनी-अपनी ऊर्जा और खनिज संपदा से समृद्ध हैं, तो वहीं भारत और चीन का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना भी उल्लेखनीय है कि ऐसे में इन सभी सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना जरूरी है। आवश्यकता है कि सदस्य देशों के बीच और भी आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए। शासनाध्यक्षों की इस बैठक में सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और निवेश को लेकर कई संधियों पर हस्ताक्षर होना है। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि एस. जयशंकर द्वारा 'मेक इन इंडिया' योजना को माडल के रूप में प्रदर्शित करने की योजना है। वस्तुत: 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम न केवल भारत, बल्कि उन तमाम विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन के उभरा है जो आर्थिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय बाजार से उपेक्षित थे। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से न केवल सदस्य देशों के बीच, बल्कि पश्चिम और अफ्रीकी देशों के लिए भी आर्थिक वृद्धि एवं निवेश के द्वार खुल सकते हैं। दूसरी तरफ, यूक्रेन संकट के बाद जिस तरह से रूस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और चीन व भारत ने रूस के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखा, सीधावना है कि इस सहयोग को सदस्य देशों के बीच विस्तारित और आगे बढ़ाने की चर्चा होगी। दूसरी तरफ, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों से नहीं, बल्कि एशिया से संचालित होती है।

वैश्विक अशांति पर चर्चा : चूंकि इस संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में सदस्यों के बीच सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति स्थापित करना है, ऐसे में हालिया अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की पूरी संभावना है। पश्चिम एशिया में इजरायल-फलस्तीन संकर्ष के बीच उपजे अंतरराष्ट्रीय हलचल ने पूरे विश्व को हैरान और परेशान किया है। वैश्विक समुदाय चाहता है कि इस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए, लेकिन महाशक्तियों के अपने निजी हित भी हैं। जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश इजरायल को लेकर सहानुभूति दिख रहे हैं, ऐसे में रूस और चीन का अन्य अरब देशों के प्रति न सही, लेकिन ईरान के प्रति समर्थन प्रकट करना आश्चर्य का विषय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईरान, शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी है। ऐसे में अन्य एससीओ सदस्यों की सहानुभूति ईरान के प्रति अपेक्षित है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से ईरान युद्ध में उलझा, उससे अन्य सदस्य देशों के बीच चिंता स्वाभाविक है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण : इस्लामाबाद में होने जा रही यह बैठक भारत और पाकिस्तान के संबंध ही दक्षिण एशिया के लिए भी खास है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई भी दक्षिण एशियाई देश इस संगठन का सदस्य नहीं है। लेकिन दक्षिण एशियाई राजनीति को प्रभावित करने वाले दो अन्य देश चीन और रूस इस संगठन के सदस्य हैं। बीते कुछ माह में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के घटनाक्रम और सत्ता परिवर्तन ने दक्षिण एशियाई राजनीति में नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसे यथार्थवादी नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। हालांकि इस बैठक में दक्षिण एशिया को लेकर कोई प्रत्यक्ष चर्चा हो इसकी संभावना न के बराबर है, लेकिन परोक्ष तौर पर इस बैठक का प्रभाव दक्षिण एशिया पर दिख सकता है।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लगभग एक सप्ताह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह यात्रा केवल एससीओ के संदर्भ में है, पाकिस्तान से किसी अन्य मुद्दे पर बात होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो विदेश मंत्री की यह यात्रा भविष्य में भारत पाकिस्तान संबंधों की बहाली स्थापित करने में मददगार साबित हो सकती है। भारत के संबंधों में सुधार को लेकर पाकिस्तान की नरमी को देखते हुए कूटनीतिक बातों की जरूरत है। भारत में सीमा पार आतंकवाद की समाप्ति के संदर्भ में एससीओ बैठक से एक नई उम्मीद जगी है। वहीं, दूसरी तरफ, एससीओ की इस बैठक से पाकिस्तान के पास भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बेहतर करने का एक अवसर है।

वैश्विक मंच पर शाकाहार की चर्चा

विजय कपूर

हान कांग सियोल में रहने वाली एक गृहिणी हैं। जब उन्हें जानवरों को काटते हुए निरंतर अनेक डरावने सपने आते हैं, तो वह गोश्त न खाने का निर्णय लेती हैं। दक्षिण कोरिया जैसे मांसाहारी देश में यह कठिन निर्णय था, जिसका उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है और वह अपने परिवार व समाज से दूर होती चली जाती हैं। इस सँक्षिप्त प्लाट को आधार बनाकर हान कांग ने 1997 में 'द फ्रूट आफ माई वुमन' नामक लघुकथा लिखी थी, जिसका उन्होंने बाद में उपन्यास के रूप में विस्तार किया जो 2007 में 'द वेजिटेरियन' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका 13 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

हालांकि हान कांग ने अपनी साहित्यिक यात्रा एक कवयित्री के रूप में आरंभ की थी। उनका पहला कविता संग्रह 1993 में प्रकाशित हुआ और फिर 1995 में उनका लघुकथा संग्रह प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने उपन्यासों पर अधिक फोकस किया। दक्षिण कोरिया की कवयित्री व उपन्यासकार हान कांग अपने देश की पहली महिला लेखिका हैं, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया के लिए यह दूसरा नोबेल पुरस्कार होगा। हान कांग को नोबेल पुरस्कार ऐसे समय दिया गया है, जब दक्षिण कोरिया की संस्कृति का वैश्विक प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। आजकल कोरियाई टीवी ड्रामा दुनियभर में धूम मचा रहे हैं। बॉंग जून-हो की फिल्म 'पैरासाइट' ने आस्कर जीता है। बीटीएस व ब्लैकपिंक जैसे के-पाप ग्रुप हर जगह दिलचस्पी एवं उत्साह से सुने जा रहे हैं।

उपन्यास लिखने के संदर्भ में हान कांग का कहना है, 'यह मेरे लिए अपने आपसे सवाल करने का तरीका है। अपनी लेखन प्रक्रिया के जरिये मैं केवल सवालों को पूरा करने का प्रयास करती हूं और सवालों में ही रहने की कोशिश करती हूं।' बहरहाल, नोबेल पुरस्कार मिलने पर उन्हें 'सम्मानित' होने का एहसास भी है और 'आश्चर्य' भी। हान कांग के पिता और भाई भी उपन्यासकार हैं, इसलिए वह कहती हैं कि उन्होंने कोरियाई साहित्य के साथ परवरिश पाई है, जिसके बहुत करीब वह स्वयं को पाती हैं। वह कहती हैं, 'मैं उम्मीद करती हूं कि कोरियाई साहित्य के पाठकों, मेरे टीचर्स और लेखकों के लिए यह अच्छी खबर है। नोबेल पुरस्कार का जश्न मैं बहुत खामोशी से मनाऊंगी।'

वैसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार की लंबे समय से इस आधार पर आलोचना होती रही है कि यह यूरोप और उत्तर अमेरिका के लेखकों पर अधिक फोकस करता है। सच ही यह पुरुष प्रधान भी है कि इस वर्ष के पुरस्कार को भी गिना जाए तो 120 में से केवल 18 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया है। हान कांग से पहले जिस महिला को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, वह फ्रांस की एनी एरनाक्स थीं। इसलिए हान कांग को यह सम्मान दिया जाना स्वागतयोग्य है। उनका शाश्वता गद्य वास्तव में प्रभावित करता है। मसलन, इन पंक्तियों को देखिए- 'सफेद रंग में सरे रंग शामिल हैं। दुनिया की सारी रोशनियां इसी में समाई हुई हैं।' हान कांग की कल्पनाओं की दुनिया में मानव मन के तारव्वानों को अपनी उंगलियों से स्पर्श करने की कोशिश है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) (ईआरसी)

खरी-खरी

प्रियतम! पुताई करने के दिन आए...

पूरन सरमा

प्रियतम, दीवाली नजदीक है। बाजार जाओ, पुताई के पैंट ले आओ और ब्रश से अपने दैलतखाने की पुताई प्रारंभ करो। देखें, हमारे बेटे ने दीवारों पर पेंसिल से तरह-तरह की रेखाएं खींच दी हैं तथा पलस्तर उखड़ने लगा है और पुरानी पुताई पपड़ी छोड़ रही है। अत: पुट्टो से दीवार की मरम्मत करो और उसके बाद पुताई का कार्यक्रम प्रारंभ करो। मजदूरी महंगी है और वे दीवाली पर हमारा दीवाला निकाल देंगे। अत: पुताई की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लो, ताकि हमारा घर-आंगन दीवाली पर चमक उठे। लक्ष्मी की कृपा भी तभी हो पाएगी।

मेरी सहेलियों ने साड़ी खरीदने के लिए बाजार का रुख कर लिया है और वे महंगी लेटेस्ट फैशन की साड़ियां इस त्योहार के लिए खरीद रही हैं। तुम भी अपने दफ्तर से फेस्टिवल एडवांस या अन्य कोई लोन लेकर मेरी इच्छाओं की पंख लगाओ। मैं ऋण करके भी घी पीने की परंपरा का निर्वाह करने वाली हूं।

गुप्ताजी को देखें, पिछले दो सप्ताह से वह पुताई कर रहे हैं और मिसेज गुप्ता खरीद-फरोख्त के लिए बाजार चली गई हैं। गुप्ता जी मुझसे स्वयं करकर गए हैं कि भाभीजी पुताई के लिए मजदूर मत लाना, शर्मा जी स्वयं अच्छा पेंट कर लेंगे।

इधर, स्वयं को बनाने में गुप्ताजी तो बार ससंदेह हो चुके हैं, लेकिन वह घोटाला करने नहीं छोड़ते। आजकल तो घोटालों का मौसम है, मौका लगे तो आप भी मेरी खातिर कोई बड़ा घोटाला कर डालो, ताकि इस मरी गरीबी से हमेशा के लिए पिंड छूट जाए। पकड़े जाने पर जेल जाना आजकल फैशन है। एकाध माह में जमानत पर छूट जाओगे और हम आराम का बैभवशाली जीवन शानो-शौकत से जी सकेंगे। इसलिए हो सके तो कुछ कर डालो। कोई बड़ा घोटाला हो हमारा भाग्य बदल सकता है। इसलिए निर्लक्ष्य और जेल की चक्की फिए बिना कहीं बड़ा हाथ साफ कर दो। ऐसा होने पर दफ्तर से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और तुम आराम से पुताई कर सको। इसलिए प्रियतम, उठो, जागो, और अपनी खाली दीवाली नजदीक है, इसके लिए सब कुछ करो और कुछ नहीं तो पुताई करो।

पोस्ट

आखिर हिंदू धार्मिक आयोजनों और यात्राओं पर ही पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? इसका क्या जवाब है।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

बहराइच मामले की रिपोर्टिंग कर रहे कुछ लोगों को रामगोपाल की जांच से ज्यादा ध्यान हटाने की घटना बड़ी लग रही है। वे उसी को तूल दिए हुए हैं।

अर्पित आलोक मिश्र@arpitalokmishra

जेंगा प्रभावित क्षेत्र में एक आइपीएस अधिकारी ने इलाके को 'मुस्लिम एरिया' कहकर संबोधित किया। उनके लिए यह सामान्य है। इससे पहले 1946 में ऐसा हुआ था, जिसका परिणाम यही निकला कि भारत को एक 'मुस्लिम इलाका' देना पड़ा। विचार्य ही वहां है कि जो डाहिड़स से सीख नहीं लेते वे उसे दोहराने को अभिशप्त होते हैं।

आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

लारेंस बिश्नोई और पप्पू यादव दोनों ही शख्स मेरे लिए नायक नहीं हैं। लारेंस बिश्नोई प्रत्यक्ष रूप से हिंसा में लिप्त है, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले यही दर्शाते हैं कि उन्होंने भी अपराध के जरिये ही राजनीति की है। ऐसे लोगों का सिर्फ जाति के नाम पर समर्थन करना तार्किक सोच के खिलाफ होगा। लाली यादव@2_rupiya

जागरण जनमत

कल का सर्वेक्षण

क्या आप मानते हैं कि संजू सैमसन ने टी-20 टीम में विकेटकीपर-ओपनर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज तक सवाल

न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट शृंखला के लिए जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कोचिंग सेंटर है खुला ले लो आकर क्लास,
गुरुवर काबिल हैं बहुतही जो आएंगे पास।
हो जाएंगे पास सीखकर काले धंधे,
भले बाद में आप चढ़ो ईडी के कंधे!
चहे कैजरीवाल उमर के बनना मेंटर,
चला रहे श्रीमान तिहाड़ी कोचिंग सेंटर!!

- ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

जयकृष्ण गोस्वामी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

दुर्गापूजा में फिर उठी टाटा के जाने की टीस

आज से 16 वर्ष पहले दुर्गापूजा के उत्सवी वातावरण में बंगाल ने टाटा जैसे 'रत्न' को खोया था। वस्तुत: तीन अक्टूबर, 2008 को दुर्गापूजा की महाष्टमी के दिन सिंगुर से टाटा की नैनो कार फैक्ट्री को तत्कालीन विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आंदोलन के कारण बाध्य होकर गुजरात ले जाने की घोषणा करनी पड़ी थी। यह घोषणा टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने भारी मन से कोलकाता में की थी। दुर्गापूजा के दौरान टाटा का जाना, वह भी 90 प्रतिशत फैक्ट्री तैयार होने के बाद, प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए आज भी अभिशप्त जैसा है। अब देश ने रतन टाटा को खो दिया। नौ अक्टूबर को दुर्गापूजा की महाष्टमी के दिन भारत का 'रत्न' दुनिया छोड़कर चला गया।

यह भी एक संयोग ही है कि 2006 में सिंगुर में लखटकिया नैनो कार फैक्ट्री लगाने के लिए टाटा को तैयार करने वाले बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का दो माह पहले ही निधन हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य व रतन टाटा, दोनों सिंगुर में फैक्ट्री नहीं लगा पाने की कसक मन में लिए दुनिया से विदा हुए। दुर्गापूजा के समय रतन टाटा के निधन ने फिर सिंगुर से नैनो के जाने की टीस उठा दी है।

वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में वामपोर्चा की भारी जीत के दिन ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 'कृषि हमारा आधार है, उद्योग हमारा भविष्य है' के नारे के साथ सिंगुर में कार फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी। समस्या फैक्टरी के लिए सरकारी पहल से भूमि अधिग्रहण को लेकर शुरू हुई। जब टाटा ने उस फैक्ट्री को गुजरात के साणंद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तब से माकपा नेतृत्व कहता रहा है कि यह केवल एक फैक्ट्री नहीं है, जो बंद हुई। इसका बंगाल के औद्योगिकीकरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। रतन टाटा ने सिंगुर छोड़ने के अपने फैसले के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने बार-बार दावा किया है कि उनका आंदोलन जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था, फैक्टरियों या उद्योगों के खिलाफ नहीं था। इसके बाद कोर्ट में भी तृणमूल जीती और चुनाव में भी ममता की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंगुर की अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस कर दी गई, लेकिन उसपर अच्छी फसल नहीं पैदा हो रही है। सवाल यह है कि टाटा के जाने के 16 वर्ष बाद भी क्या बंगाल की ममता सरकार उद्योगों को लेकर अपने छवि को सुधार पाने में कामयाब हुई?

कोलकाता में 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य (बाएं) के साथ रतन टाटा। फाइल

इससे पहले कि हम मौजूदा स्थिति पर चर्चा करें, आइए अतीत पर नजर डालें। जिस तरह रतन टाटा के निधन की खबर महाष्टमी की रात आई, उसी तरह 16 साल पहले महाचतुर्थी की शाम को दुर्गापूजा में सिंगुर से उनके (टाटा) जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2008 में सांसद ममता बनर्जी उस शाम (तीन अक्टूबर) पार्क सर्कस में दुर्गापूजा पंडाल का उद्घाटन कर रही थीं, जब फैक्ट्री बंद होने की खबर आई तो सिंगुर में गुस्सा भड़क गया और एक्सोसेवे पर टायर जलाए गए। उनकी (ममता) प्रतिक्रिया थी- 'अगर टाटा चले गए तो यह उनका निजी मामला है। हमें इसकी परवाह नहीं है।'

उसी रतन टाटा के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार रात गहरा दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या तृणमूल की स्थिति पर कोई पुनर्विचार हुआ है? पार्टी नेता कुणाल घोष का कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि माकपा की गलत भूमि नीति की जिम्मेदारी ममता दीदी पर नहीं डाली जानी चाहिए। सिंगुर में टाटा को जमीन दिए जाने पर पहले ज्योति बसु, माकपा की कृषक सभा और वामपोर्चा के सदस्यों ने विरोध जताया था। पहला विरोध तृणमूल ने नहीं किया था। यह ओद्योगन कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ था। टाटा के खिलाफ तृणमूल नहीं थी। यह टाटा समूह ही था, जिसने व्यावहारिक रूप से विज्ञापनों में माकपा का समर्थन करने की अपील करके इस मुद्दे को राजनीतिक आयाम दिया। सिंगुर के आंदोलन के बाद पूरे देश में नीति में बदलाव आया। माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा- 'तृणमूल ने उस कारखाने को बंद कराके बंगाल का अपमान किया, जो पूरा होने वाला था, लेकिन यह गुजरात के लिए अच्छा था। मुझे नहीं पता कि वर्तमान मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी में यह आकलन करने की क्षमता है कि बंगाल को इसके परिणामस्वरूप दीर्घावधि में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?'

एक और दुर्गापूजा का समापन हो गया। बुद्धदेव भी नहीं रहे और रतन टाटा भी चले गए, फिर भी प्रश्न और बहस अब भी यथावत है। कुछ बहस कभी खत्म नहीं होतीं। यह घाव इतना गहरा है कि टीस वक्त-बे-वक्त उठती रहेगी।

मंथन

मादक पदार्थों पर निर्णायक प्रहार

तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि से होते हुए नशे के मामले हेरोइन और कोकेन जैसे खतरनाक ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है, जिस पर जल्द अंकुश लगाया जाना चाहिए

ख. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले कुछ दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्रग्स के कई बड़े मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा, रविवार को गुजरात से भी पांच हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की गई है। इससे अलावा, छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। वहीं अक्टूबर 2022 में केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र से दो सौ किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन पकड़ी गई। जिस प्रकार विभिन्न मामलों में अलग-अलग प्रदेशों व देशों के लोगों की संलिप्तता इसमें उजागर हो रही है, उससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित और व्यापक कारोबार बन चुका है।

किसी भी प्रकार का नशा जहां एक ओर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक है, वहीं समाज और राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। नागरिक किसे भी समाज एवं राष्ट्र की अमूल्य निधि एवं उसके विकास की मूल कड़ी होते हैं। यदि यह नागरिक ही नशे अथवा ड्रग्स की चपेट में आ जाएंगे तो फिर राष्ट्र विकास कैसे संभव है? चिंतातनक यह भी है कि घुसपैठ, ड्रोन, समुद्री मार्ग आदि के जरिए भिन्न-भिन्न रूपों में पड़ोसी देशों से नशा भारत में भेजा जा रहा है। क्या यह वैश्विक पटल पर ताकतवर बनते भारत को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश नहीं है? आज नशे के मकड़जाल में लगभग पूरा देश फंसता जा रहा है। यह भी सर्वविदित है कि नशे का अवैध कारोबार अधिकतर समुद्र तटीय प्रदेशों से होकर देशभर में फैल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय तस्कर लगभग 60 में से 70 प्रतिशत ड्रग्स समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचा रहे हैं। यद्यपि गृह मंत्रालय प्रत्येक मोर्चे पर ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है, तथापि ड्रग्स तस्करी के मामले गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष उच्चस्तरीय ड्रग्स निवारण समिति हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट की जा रही है।

देश को खोखला करने की साजिश : ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा भारत को ड्रग्स के जरिए खोखला करने की भी साजिश हो रही है। ड्रग्स तस्कर मोटी कमाई के लिए छात्रों और युवा वर्ग को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं। ये तस्कर उच्च शिक्षा केंद्रों व विश्वविद्यालयों में ड्रग्स खपा रहे हैं। यहां यह भी समझने की आवश्यकता है कि देश के विद्यालय और महाविद्यालय युवाओं के शिक्षा और विभिन्न गतिविधियों के केंद्र हैं। उनके आसपास नशे और ड्रग्स की खपत होना देश के विकास की राह में बड़ी बाधा बन सकती है। ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल अफीम उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अफगानिस्तान में होता है। इससे ही प्रक्रिया स्वरूप हेरोइन समेत अनेक नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। क्या आज यह आक्रयक नहीं है कि ड्रग्स तस्करी पर निर्णायक लड़ाई के लिए नीति बनाकर अंतरराष्ट्रीय समन्वय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए।

गांधी जी ने अप्रैल 1929 के यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में लिखा था कि जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है कहना चाहिए कि उसके सामने बिनाश मुंह बाए खड़ा है। अब मामला शराब से आगे बढ़ता जा रहा है। क्या आज गांधी जी की इस चेतावनी पर गंभीरता से विचार करने की आक्रयकता नहीं है? क्या आज गंभीर चुनौती बनते ड्रग्स के मामलों में विभिन्न राज्यों को समेकित रूप में योजना बनाकर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्य यह भी सत्य नहीं है कि ड्रग्स के विभिन्न अवैध धंधें में कुछ राजनेताओं और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत भी उजागर हो चुकी है? क्या भिन्न-भिन्न प्रकार के नशे और ड्रग्स के बढ़ते मामलों के लिए लचर न्याय व्यवस्था और कठोर दंड का प्रविधान न होना नहीं है? क्या आज हमें यह नहीं समझना चाहिए कि नशा निराश, अवसाद एवं जीवन का अंत लेकर आता है?

चिंताजनक यह भी है कि आज नशे की गिरफ्त में केवल युवा अथवा पुरुष ही नहीं हैं, अपितु महिलाएं और छोटे-छोटे अबोध बालक भी इस लत के शिकार होने के साथ-साथ इस कारोबार में झोंके जा रहे हैं। नशे के कारोबार से तस्करों को खूब धन मिलता है। कुछ जगह राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। लेकिन आज एक कड़े रुख में यह समझने की आक्रयकता है कि पूरे देश में महामारी की तरह फैलते ड्रग्स के मामले युवा भारत और विकसित भारत के संकल्प में बड़ी बाधा हैं। आज यह भी आक्रयक है कि इन विषयों पर समाज और शिक्षण संस्थानों में व्यापक चर्चा हो। जन-जन को जागरूक किया जाए। भारतीय दंड संहिता में ड्रग्स के मामलों में पकड़े जाने पर कठिन और त्वरित दंड के प्रविधान किए जाएं। ड्रग्स जीवन के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और विकास के लिए भी बड़ा खतरा हैं तो ड्रग्स तस्करी के लिए मृत्युदंड का प्रविधान क्यों नहीं होना चाहिए?

देश के अनेक हिस्सों से निरंतर हो रही ड्रग्स की बरामदगी। फाइल

Dainik Jagran www.jagran.com Dainik Jagran Hindi National Daily

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024

हत्या से उपजे सवाल

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और नेता बाबा सिद्दीकी की विजयादशमी के दिन मुंबई के बांद्रा में हुई हत्या अगर आपराधिक सबसे बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में उभरती दिख रही है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। विधानसभा चुनावों के ऐन पहले हुई इस हत्या ने न केवल सबको सकते में डाल दिया बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या देश की वित्तीय राजधानी एक बार फिर गैंगवॉर और अंडरवर्ल्ड के खौफ वाले दौर का गवाह बनने जा रही है।

नब्बे के दशक का दौर | सड़कों पर शूटआउट, गैंगवॉर और बड़े कारोबारियों, बिल्डरों, फिल्मी हस्तियों को धमकियां, वसूली, यहां तक कि हत्या भी मुंबई के लिए कोई नई बात नहीं है। नब्बे के दशक के उस दौर की यादें आज भी आम मुंबईकरों के मन से मिटी नहीं हैं। लेकिन कुछ तो मुंबई पुलिस की सख्ती और कुछ आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में आए बदलाव ने उस दौर को अतीत के हिस्से का रूप दे दिया।

अंडरवर्ल्ड के दौर की वापसी?

पुलिस तंत्र की कमजोरी | सिद्दीकी की हत्या से वही डरावना अतीत अचानक वर्तमान में दस्तक देता महसूस हुआ। जिस तरह पहले से भयभीत देकर और Y-लेवल पुलिस सुरक्षा को भेदते हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल के साथ ही पुलिसिया तंत्र की कमजोरी भी दर्शाता है।

हत्या का असल मकसद | शुरुआती रिपोर्टों में अपराध को अंजाम देने और उसकी जिम्मेदारी लेने के अंदाज के आधार पर इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत बताया जा रहा है। हो सकता है यह सच हो, लेकिन 'सलमान खान का साथ देना' इतनी बड़ी वारदात का कारण होगा, यह मानना मुश्किल है। ध्यान रहे, इन चुनावों में खतरों री-डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट एक बड़ा मुद्दा है। खुद बाबा सिद्दीकी भी ईडी जांच के घेरे में थे। उन पर महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पद के दुरुपयोग का आरोप था। इस मामले में 462 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच से हत्या के असली कारणों का खुलासा होगा।

कानून-व्यवस्था की कसौटी | मगर सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं देने की। हाल के दिनों में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई जिनसे यह संकेत गया कि पुलिस-प्रशासन की कानून-व्यवस्था पर पकड़ कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना के बाद सबसे पहले यही कहा कि गैंगवॉर जैसे हालात किसी भी सूरत में नहीं बनने देना है। उनके ये शब्द ही सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी कसौटी होंगे।

धूप-छांव

जस्ट अ नंबर?

प्रणव प्रियदर्शी

एक समय होता है जब कोई हमारी उफ़ कुछ महीने भी कम करके बता दे तो बदहवास नहीं होता। एक बार किसी खेल के सिलसिले में बच्चों को दो समूहों में बांटते हुए दीदी ने मुझे सात साल के बच्चों वाले ग्रुप में डाल दिया था, जबकि मैं आठ साल पूरे कर चुका था। मैं तत्काल शिकायत लेकर मां तक पहुंच गया। उनके हस्तक्षेप के बाद दीदी ने यह घोषणा करके मुझे राहत दी कि वैसे तो यह बड़ा है, आठ साल का हो गया है, लेकिन चूंकि आठ साल के लड़कों वाला कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए अभी सात साल वाले ग्रुप में ही रहेगा। अब मैं संतुष्ट था। ग्रुप नहीं बदला तो क्या, सब यह तो जान गए कि मैं आठ साल का हूं, कोई बच्चा नहीं।

मगर उम्र के तीसरे दशक तक आते-आते यही मनःस्थिति पलट जाती है। तीस साल का हो जाने की कल्पना बहुतों को डराने लगती है। आम तौर पर यह रोग लड़कियों का माना जाता है लेकिन लड़के भी इससे अछूते नहीं होते। तीस साल के आसपास मन के जो भाव अक्सर खुद से भी छुपे होते हैं, 40 का होते-होते इस कदर बेनकाब हो जाते हैं कि लाइफ क्रिसिस एट फॉर्टी जैसे मुहावरों में तसल्ली तलाशनी पड़ती है। कोई एक बार कह दे कि आप तो तीस से ज्यादा के नहीं लगते, तो मन बल्लियों उछलता रहता है देर तक। यहां तक कि दो दशक आगे के लोगों ने भी अपने लिए यह मुहावरा गढ़ रखा है कि मर्द तो साठा पर पाठा होते हैं। इससे आगे-पीछे के स्त्री-पुरुषों के लिए सटीक्रांत मुहावरा है- एज इज जस्ट अ नंबर।

आखिर हम उम्र को झुठलाने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? क्या इसलिए कि अंदर ही अंदर यह सचाई खाए जाती है कि हमारा शरीर धीरे-धीरे अपनी क्षमता खोता जा रहा है, कि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं? अगर यह सच है तो मन इस सचाई को स्वीकार करने से भयराता क्यों है? क्या इसलिए कि शरीर के जरिए मिला यह जीवन मन के लिए आफी नहीं होता? एक राउंड बचपन, एक राउंड जवानी, एक दौर के दोस्ती, प्यार, रिश्ते- मन को संतुष्ट नहीं कर पाते? क्या यह वही चीज है जिसे आशा-तृष्णा का एक रूप बताते हुए कबीर ने कहा है, 'माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। आसा-तृसना ना मुई, यों कहि गया कबीर।।'

या इसका हमारे ईगो से भी कोई मतलब है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व, अपने रूप और बुद्धि-बल-चातुर्य से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों के सोच-समझ-व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं और उस के असर को अनदेखा करने की कोशिश राह के एक रोड़े को दूर करने की प्रक्रिया भर है?

बोल वचन

देस बिराना है

बचपन में जब मेरी बहनें मुझे मुंह बिराएं यानी मुंह बना-बनाकर चिढ़ाएं तो मैं रोते हुए अम्मा के पास पहुंचूं। मोटे-मोटे आंसू अपने आंचल से पोंछकर अम्मा बोलें, जाने दो उन लोगों को। जो ज्यादा बिराता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अब से तुमको कोई बिराए तो यही बोलना कि तुम्हारा मुंह ऐसे ही टेढ़ा हो जाएगा। अवध से लेकर बघेलखंड तक बिराने का पहला मतलब अगर कुछ होता है तो यह है चिढ़ाना। शब्दकोश कहता है कि बिराना अगर अकर्मक है तो उसमें बस मुंह टेढ़ा करके या जीभ निकालकर आंख नचाकर ही काम चल जाता है। लेकिन यह बिराना अगर सकर्मक है तो इसमें मुंह ही नहीं, समूची देह भी शामिल हो सकती है। यह बिराना किसी की नकल करके चिढ़ाना होता है। मसलन, कोई हकलाता हो तो उसके सामने उसकी नकल करना उसे बिराना होता है। बिराना शब्द का स्रोत संस्कृत में वी धातु में ही है, कुछ-कुछ फरसी में भी मिलता है। लेकिन यहां बिराना का मतलब चिढ़ाना नहीं होता, बल्कि बेगाना होता है। जो अपना ना हुआ, वो बिराना हो गया। सबद में कबीरदास कहते हैं, 'रहना नहिं देस बिराना है। यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है'। विनयपत्रिका में तुलसीदास भी कहते हैं, 'ऐसोहि जनम-समूह सिराने। प्राननाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन बिराने'। नहीं कन्नौज में बिराना यानी बेगाना बिराना बन जाता है तो गढ़वाल में बिराणा। बिराना पर ही सूरज प्रकाश का उपन्यास है- देस बिराना। इस उपन्यास का हीरो परेशान होकर परांए देस चला जाता है। किसी की नकल करके बिराने के लिए इंग्लिश में mock शब्द है तो बेगाने के लिए stranger शब्द है। लेकिन ये दोनों ही शब्द बिराना के उस भाव तक नहीं पहुंच पाते, जिन्हें लोक ने ग्रहण किया है।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अप्रिय घटनाओं के सिलसिले ने भारत की नाराज़गी बढ़ा दी है

दिल्ली अब भी बहुत दूर है ढाका के लिए

कल्लोल चक्रवर्ती

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस को लगभग सवा दो महीने में दूसरी बार ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर जाना पड़ा। दुर्गापूजा के दौरान कुछ मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को आश्वस्त करने के लिए यह मंदिर पहुंचे थे। इससे पहले, अगस्त में शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भारत में शरण लेने के बाद जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, तब भी वह ढाकेश्वरी मंदिर गए थे।

पूजा पर हमले | यूनुस के आश्वासनों पर लेकिन बहुत भरोसा नहीं जगता। बांग्लादेश में दुर्गापूजा के ज्यादातर पंडालों में इस बार CCTV के साथ पहरे की भी व्यवस्था थी। इसके बावजूद ढाका के तांतीबाजार स्थित एक पंडाल में पेट्रोल बम फेंका गया। घटनास्थल के ठीक सामने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का दफ्तर है। इससे पहले भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चटगांव के जैनपुर सेन हॉल में आयोजित दुर्गापूजा में सांस्कृतिक आयोजन के दौरान जमात-ए-इस्लामी से जुड़े एक संगठन ने इस्लामी संगीत पेश किए, जिसका संदेश यह था कि सबको इस्लाम अपना लेना चाहिए।

भारत की आपत्ति | इसी तरह सातखीरा जिले के श्यामनगर में देवी यशोरेश्वरी का मुकुट दिनदहाड़े जिस तरह चोरी चला गया, वह तो बहुत आश्चर्यजनक है। 100 तोले सोने का वह मुकुट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में दान किया था। इसके अलावा भी अनेक जगह पूजा बाधित करने की कोशिशें हुईं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले खुलना जिले के कई मंदिर प्रबंधन ने पांच लाख रुपये का टैक्स चुकाने की धमकी भरी चिट्ठियां मिलने का दावा किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुर्गापूजा के दौरान वहां हुई इन घटनाओं पर सख्त आपत्ति जताई है।

दुर्गापूजा की शुरुआत | बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर अब भले ही 1.3 करोड़ रह गई हो, लेकिन दुर्गापूजा उनके लिए अपनी स्मृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है। दुर्गापूजा की शुरुआत ही आज के बांग्लादेश में हुई थी। ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कहते हैं। यहां 800 साल से दुर्गापूजा हो रही है।

हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि बंगाल में पहली बार दुर्गापूजा का आयोजन 1583 ईस्वी में राजशाही जिले के ताहिरपुर में राजा कंस नारायण ने किया था। कोलकाता में दुर्गापूजा का आयोजन इस के बाद ही शुरू किया जा सका था।

पुरानी समस्या | शेख हसीना भी दुर्गापूजा के पंडालों को सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं रही थीं। वर्ष 2021 में पूरे बांग्लादेश में 50 से अधिक पूजा पंडालों पर हमले बोले गए थे। दुर्गापूजा के दौरान अजान के समय लाउडस्पीकर धीमा करने का निर्देश शेख हसीना के प्रधानमंत्री काल में भी बदस्तूर जारी किया जाता था। लेकिन तब पंडालों पर हमला बड़ा मुद्दा अमूमन नहीं बनता था, क्योंकि शेख हसीना की भारत समर्थक छवि थी। मोहम्मद यूनुस की छवि ऐसी नहीं।

कट्टरपंथी सक्रिय | अंतरिम सरकार आने के बाद बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर की सक्रियता बढ़ गई है। यह संगठन आतंकी हमलों के जरिये दुनियाभर में खिलाफत की प्रतिष्ठा की मंशा पाले हुए है। वहीं जमात-ए-इस्लामी नए निजाम में है ही। बांग्लादेश में चुनाव कराने और नई सरकार के गठन के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बेगम खालिदा जिया की बीएनपी से भी संपर्क साधा जा रहा है। इन दोनों की छवि कट्टर भारत विरोधी की है।

रवैये से नाराजगी | शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से ही भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट महसूस की जा रही है। अंतरिम सरकार का दायित्व संभालने के बाद एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब तक शेख हसीना भारत में हैं, तब तक वह अपना मुंह बंद रखें। इस बयान से भारत खुश नहीं था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के कारण भी भारत खुश्श है। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक, विगत चार अगस्त से 20 अगस्त तक वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले के 2,010 मामले सामने आए थे।

मुलाकात नहीं | मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी के साथ अभी तक द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान यूनुस ने पीएम मोदी के साथ बैठक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय पक्ष की अनिच्छा के कारण ऐसा नहीं हो सका। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने यूनुस सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी।

अधूरे प्रयास | सितंबर में प्रतिबंध लगाने के बावजूद यूनुस सरकार ने दुर्गा पूजा से ठीक पहले 3000 टन हिल्सा मछलियां भारत भेजीं। अंतरिम सरकार ने दुर्गापूजा में एक दिन के बजाय दो दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की। लेकिन दुर्गापूजा के दौरान घटी घटनाएं बताती हैं कि सरकार को इसका लाभ नहीं मिला, उल्टे छवि बन रही है कि कट्टरपंथियों के साथ होने के कारण वह अल्पसंख्यकों का भला नहीं कर सकती। ऐसे में, भारत के साथ अपने रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश को अभी और कोशिशें करनी होंगी।

मेन आईटम से जास्ती झक्कास साइड इफेक्ट

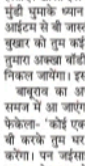
दीपक पापपोर

बाबूराव कूं तुम जानताए न? तो अपुन का खाली बेस्ट फ्रेंड नई होताए, भिड़! बोले तो फिलॉसफर अकर गाइड भी होताए। अपुन उस्कूं पूछा- 'बॉस, अपुन कूं समज नईं आताए जबी कोई भी इलेक्शन होताए- तबी इलेक्शन का बख्खत में उस्ता भयभाय नई होताए जित्ता उस्का बाद होताए। अईसा काएकूं?'

दिलीप कुमार का माफिक सीरियस पोज लेके बाबूराव अपुन कूं बोलताए- 'बॉस, अईसा अक्खा आईटम का भीतर होताए। खाली इलेक्शन का भीतर नईं। अबी तुम इदर-उदर मुंडी घुमाके ध्यान से देखेगा, तबी समज जाएंगा कि मेन आईटम से भी जास्ती झक्कास उस्का साइड इफेक्ट होताए। बुखार को तुम कईसा भी करके झेल लेगा पन उस्का बाद तुमारा अक्खा बॉडी सॉलिड दरद करेगा। आई श्पथ्थ, जान निकल जायेंगा। इसकूं बोलताए बुखार का साइड इफेक्ट।'

बाबूराव का अच्छा आदत बोले तो तुमकूं कोई बात समज में आ जाएंग तबी बी समजाएंग। दो दूसरा आईटम फेकेला- 'कोई एक्साईट में तुमारा हात-पांव टूटेगा। कईस बी करके तुम थर पहुंचेगा। तबी तलक तुम दरद सहन करेगा। पन जईसाईच तुम थर कूं पहुंचेगा, तुमारा लब्बेत एकदम से खराब होएंगा। हॉस्पिटल पहुंच के तुम अकर जॉर से बोमाबोम करेगा। अबी तुम कूं समज में नई आएंगा कि तुम कईसा टूटेला हात-पांव लेके थर पहुंचेला, हॉस्पिटल पहुंचेला। तबी तलक दरद नईं होएंगा। पन थर वाला कूं देखेगा नईं तो डॉक्टर कूं देखेगा तबी स्सीलिड दरद होएंगा। इसकूं बोलताए फ्रेक्चर का साइड इफेक्ट।'

AI image

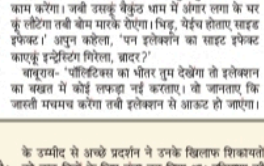

बाबूराव तीसरा आईटम दिएला- 'अबी अपुन का घर का कोई मर जायेंगा तबी उस टाइम पे तुमकूं मय्यत अकर काठी का इंतजाम करना मांगताए। इस करके तुम मुंडी नीचे करके काम करेगा। जबी उस्कूं बैकुंठ धाम में अंगार लगा के घर कूं लौटेगा तबी बीच मारके रीएंगा। भिड़, मैईय्या होताए साइड इफेक्ट।' अपुन कहेला, 'पन इलेक्शन का साइड इफेक्ट काएकूं इन्ट्रेस्टिंग गिरेला, ब्रादर?'

बाबूराव- 'पॉलिटिक्स का भीतर तुम देखेगा तो इलेक्शन का बख्खत में कोई लफड़ा नईं करताए। तो जानताए कि जास्ती मयभय करेगा तबी इलेक्शन से आऊट हो जाएंगा। सब लोग चुप मर बइठेंगा। तो अपना टोटल गुस्सा निकालेगा इलेक्शन का बाद। कोई बोलेगा अपुन का पास पार्टी का फंड नईं पहुंचेला, अण्ण्श्य खाएला। कोई हल्ला करेगा कि उसकूं टाइम पे किसी का मदद नईं मिल्ला इस करके वो हारेला। कोई कूं पार्टी निकालेगा तो कोई कूं नोटिस देगा। कोई कूं पद से हटाएंगा नईं तो कोई कूं 6 साल का वास्ते पार्टी से सस्पेंड करेगा। इलेक्शन का टाइम तुम जित्ता बोरिंग, इलक्शन का बाद तुमकूं उत्ताईच झक्कास स्टोरी सुनने कूं मिलेगा।'

बाबूराव से अपुन जबी कहेला कि, 'इलेक्शन खल्लास होने का बाद अईसा स्टोरी का अपुन क्या करेंगा, भिड़? अपुन कूं तो इलेक्शन का टाइम पे स्टोरी मांगताए कि कउन किसका तंगड़ी खिंचेला, कउन किसकूं भोका दिएला। अबी तुमारा इलेक्शन का टाइम पे पब्लिक कूं ये सब जानना मांगताए न? बाद में उसका क्या करने का?'

बाबूराव- 'तुम ये बात कूं ठीक से समज के लेने का! कोई बी साल का इलेक्शन पिछला इलेक्शन का साइड इफेक्ट होताए। कंट्री का भीतर कोई भी इलेक्शन होन दो, वो पैला वाला इलेक्शन का साइड इफेक्ट होएंगा। पंचायत इलेक्शन का साइड इफेक्ट तुमकूं नगर पंचायत इलेक्शन में देखने कूं मिलेंगा। नगर पंचायत का विधानसभा अकर विधानसभा का लोकसभा इलेक्शन में दिखेंगा। जास्ती झक्कास आईटम करूंन सा होताए- थोड़ा समज के थोलने का! पंचायत का कि लोकसभा का?'

शेयर करें अपने अनुभव

आप मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सम्पेक्ट में लिखें- 'खाली पीली'

ट्रंप से BJP की दूरी

पूरा विश्व अभी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में भी अगले महीने चुनाव होने हैं। वहां डॉनल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। इसी बीच, दिल्ली BJP के नेता विजय जॉली ने ट्रंप के पक्ष में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने विवाद खड़ा कर दिया। BJP के विदेश विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर पोस्ट कर साफ किया कि विजय जॉली की ओर से ट्रंप के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम का BJP से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने लिखा - BJP स्पष्ट मत रखती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव उसका आंतरिक मामला है और पार्टी किसी उम्मीदवार का न तो समर्थन करती है और न ही विरोध। हालांकि उनके बयान के बाद भी विजय जॉली झुकने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसी से प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है और वह ट्रंप का समर्थन करते रहेंगे क्योंकि ट्रंप नरेंद्र मोदी और भारत के समर्थक हैं। पिछली बार ट्रंप के पक्ष में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी सवाल उठे थे। ऐसे में BJP इस बार पूरी तरह सतर्क है और चुनाव से दूरी बनाकर रखे हुए है।

हरियाणा में हार की गूंज

हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार ने कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया है। इसके लिए पार्टी के दो सीनियर नेता विशेष रूप से सबके निशाने पर हैं। उन दोनों पर आरोप है कि वे राहुल गांधी तक सही फीडबैक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और पार्टी में मनमाने तरीके से फैसले कर रहे हैं। हालांकि, ये दोनों आम चुनाव से पहले ही कई नेताओं का टारगेट बने हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस के उम्मीद से अच्छे प्रदर्शन ने उनके खिलाफ शिकायतों को कुछ दिनों के लिए ठंडा कर दिया था। हरियाणा की हार ने इस दबे हुए गुस्से को फिर सतह पर आने का मौका दे दिया है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि न सिर्फ अंदर के गलत फैसलों के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं बल्कि सहयोगियों के साथ रिश्ते बिगाड़ने में भी इनके ईगो का बड़ा योगदान है। दरअसल, दोनों नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इनके विरुद्ध खुलकर मोर्चा खोलने से सभी हिचकते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अचानक जिस तरह से पार्टीजनों की भावनाएं बाहर आने लगी हैं, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर इन नेताओं के खिलाफ भी आवाज उठने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला।

जाति जनगणना पर मंथन

अगले कुछ दिनों में देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार को यह बड़ा फैसला लेना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं। विपक्ष इसके लिए लगातार दबाव बना रहा है। खुद BJP के सहयोगी दल इसके पक्ष में हैं। लेकिन माना जा रहा है कि BJP के अंदर इस मसले पर एक राय नहीं है। संघ भी इस मुद्दे पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि इसका असर किस तरह का होगा। यही कारण है कि जनगणना का मसला पिछले कुछ महीनों से लगातार टाला गया। लेकिन अब इसके और टालने की सूरत नहीं दिख रही है।

DMK से रिश्ता

अब तक I.N.D.I.A. ब्लॉक में सबसे मजबूत कांग्रेस और DMK का साथ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर लोकसभा चुनावों में इसकी मजबूती बखूबी देखी गई, और मानी भी गई। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई भी रिश्ता स्थाई नहीं होता। हालत कुछ यूं हैं कि इस रिश्ते पर अब वहां भी सवाल उठे रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के कई नेता विधानसभा चुनाव में DMK से गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ने या छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि DMK सरकार के खिलाफ तमिलनाडु भर में एंटी इनकंबेंसी फैक्टर है। अगर दोनों दल साथ मिलकर लड़े तो उसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही, वे मानते हैं कि आज की तारीख में जब विपक्ष का कोई भी दल मजबूत नहीं दिख रहा है, तो यही मौका है जब पार्टी को वहां अपने दम उतने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के एक सीनियर सांसद लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि उनकी बात मानने को अभी केंद्रीय नेतृत्व किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। फिर भी पार्टी सांसद अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे हैं। वहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

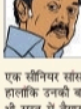

चौहान पर निगाहें

अब किसी भी समय झारखंड में विधानसभा चुनाव का एलान हो सकता है। इस बार वहां BJP की तैयारी एकदम अलग दिख रही है। पहली बार वहां पार्टी के लिए चुनाव तैयारियों का जिम्मा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। वहीं चौहान भी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने चुनाव की तैयारियों की पूरी कमान ले भी ली है। पार्टी के अंदरखाने कहा जा रहा है कि चुनाव में टिकट वितरण से लेकर प्रबंधन की पूरी देखरेख मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम की निगरानी में हो रही है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस चुनाव के तुरंत बाद BJP में नए अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। जब उन्हें मध्य प्रदेश में मिली जीत के बावजूद सीएम नहीं बनाया गया था, तब कहा गया था कि वह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान संघ की पसंद भी माने जाते रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड चुनाव परिणाम पर सबकी नजर बनी हुई है। ये परिणाम पार्टी के अंदर के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

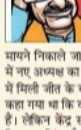

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

फूल से अगर फल बनना है तो टकराव को छोड़ना होगा

निर्मल जैन

फल बनने के लिए फूल अपनी सारी पंखुड़ियां अपने से अलग कर देता है। हमें भी अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो अपने टकराव, ईर्ष्या-द्वेष रूपी विकारों की सभी पंखुड़ियों को अपने से अलग कर देना होगा। ऐसा करके हम कुछ खोते हैं। इसके उलट, ऐसा करके अपने से और बड़े आकार को पा जाते हैं। लेकिन अगर पंखुड़ियां अलग नहीं करते, टकराव का जवाब टकराव से देते हैं तो अपना बिखराव तो करते ही हैं, अपनी जगह और सम्मान भी खो देते हैं। हमारे सभी महापुरुष विरोध नहीं सामंजस्य के मार्ग पर चल कर ही मानुस से मनीषी कहलाए।

जीवन में सामंजस्य और समाधान का फव्वारा चलता रहेगा तो हर सुबह सम्यक खोज की गंगोत्री किलोमें करती नजर आएगी। खुद को जिंदगी के हर मोड़ पर समझ की खिड़की खोलने के लिए हमेशा तैयार रखना है। समझ आ जाए तो टकराव की हर स्थिति में समझौता संभव है। जब भी संघर्ष की स्थिति हो सामंजस्य के 'पावर पॉइंट' से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि छोटी प्रतिकूलता के क्षण में उपेक्षा का चश्मा पहन लें। जब वही प्रतिकूलता सामने आए तो समझदारी से अपनी सुरक्षा करें।

बांस की आपसी टकराहट से ही दावानल का विकराल रूप धर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं। जीवन में भी आपसी टकराहट सुख को भस्म कर देती है। जहां सामंजस्य है, समझ है वहां सहयोग है, शांति है। टकराव में सदा संघर्ष है। संघर्ष में बैर-विरोध, द्वेष, कटुता आदि का फैलाव है जो विनाश का रास्ता दर्शाता है। हम आजाद हैं कि अपनी ताकत, मेहनत और वक्त को टकराव में लगाएं, या सहयोग में करें। हम हर समय खुद से भी समझौते करते हैं। हमारा शरीर कुछ चाहता है जबकि मन कुछ और करने पर आमादा होता है। ऐसे में अपने मन और शरीर, दोनों पर काबू करना आसान नहीं है। किसी एक को समझाना पड़ता है।

हम अपने मन और शरीर में समझौता करा सकते हैं तो किसी और से सम्मानपूर्वक समझौता करने में हिचक कैसी? हर किसी को अपने हिसाब से चलाया नहीं जा सकता। जो सबको अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं उनका जीवन केवल खाद-विवाद और लड़ाई -झगड़ा करते हुए बीतता है।

सदैव मनमाफिक माहौल में रहना और विषम स्थितियों में किया समझौते करे जिंदगी जीना कोरी कल्पना है। जिंदगी समझौते का ही दूसरा नाम है। जो समझौते नहीं कर पाते उनके लिए किसी भी रिश्ते में बने रहना मुश्किल होता है।

नदी भी कभी ऊंचे-नीचे पर्वतों, कभी रेगिस्तानी रास्तों को पार करती है। वह सबसे समझौता करते हुए सागर में विलीन होकर खुद सागर बन जाती है। हमें भी अगर उस विशाल में समाना है तो उस तक पहुंचने की बाधाओं को समझपूर्वक सुलझाना है। जो गलत है, वह गलत है, उसका विरोध होना ही चाहिए। समझौते करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी का सौदा कतई नहीं करना है। सब के जीवन में शांति बनी रहे इसके लिए अपनी मानसिक शांति को भी नहीं खोना है। समझदारी से किए हुए हमारे समझौते लोगों के ही नहीं, खुद हमारे होठों पर भी मुस्कुराहट बनाए रखते हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ पर्दे के पीछे का सच

पहली अक्टूबर को खाली-पीली कॉलम में प्रकाशित लेख 'चांद वाला दिखेगा नई, पन काम करोक देगा' पढ़ा। आजकल राजनीति और सत्ता के खेल में जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर एक विचार बार-बार मन में आता है कि क्या जनता द्वारा चुने गए नेता ही वास्तव में सभी फैसले लेते हैं? हमारे समाज में यह आम धारणा है कि नेता, जैसे कार्पोरेटर, विधायक, सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। लेकिन सचाई यह है कि जब कोई नेता चुनाव जीतता है, तो उसके साथ अक्सर कोई और शख्स पर्दे के पीछे काम करता है।

प्रतीक मिश्रा 'प्रीतम', चुरड़ी

■ जिम्मेदारी दिखाए बांग्लादेश

संपादकीय 'सबकी सुरक्षा जरूरी' (14 अक्टूबर) पढ़ा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमले न केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इनका प्रभाव पड़ सकता है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश सरकार तुरंत सख्त कदम उठाए और ऐसे तत्वों को कड़ी सजा दे जो समाज में हिंसा और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

राजेश चोपड़ा, लक्ष्मी नगर

■ हत्या का महिमामंडन

कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों के जमानत पर छूटने के बाद उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, वह वाकई निंदनीय है। हमारे देश में हत्यारों, बलात्कारियों के जेल से छूटने पर उनका स्वागत और महिमा मंडन किया जाना कोई शुभ संदेश नहीं है। हो सकता है हम किसी के विचारों से सहमत न हों, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी हत्या कर दें। गौरी लंकेश के लेखन व तर्कों से असहमति हो सकती है, मगर असहमति का जवाब तर्कों व तथ्यों से दिया जाता है, ना कि गोली से।

हेमा हरि उपाध्याय, इंमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रैफिक जाम से दिल्ली की हवा हुई खराब- एक खबर
– वह दिन दूर नहीं जब पेड़ों को भी मास्क पहनने होंगे।

महिमा यादव

सम्पादकीय

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां अति नियमन और छोटे संयंत्रों का जाल

विनिर्माण क्षेत्र में, खासतौर पर श्रम आधारित विनिर्माण में भारत का निरंतर कमजोर प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मुद्दा है। यह कोई पहेली भी नहीं है बल्कि इस बात को कई तरह से समझा जा सकता है और इसकी कई संभावित वजहें और स्पष्टीकरण हैं। व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव, खराब लैंगिक संबंध और दिकाकदेह कानून व्यवस्था और निष्प्रभावी शैक्षणिक और कौशल व्यवस्था आदि सभी की इसमें भूमिका है। परंतु लंबे समय से माना जाता है कि इसकी वजह अत्यधिक नियमन है। खासतौर पर श्रम और रोजगार के क्षेत्र में अति नियमन। बीते कम से कम दो दशक से देश में कंपनियों के आकार पर नियमन के असर को समझा जाता रहा है। श्रम नियमन के कारण प्रति इकाई श्रम की लागत एक तिहाई से अधिक बढ़ जाती है और अत्यधिक नियमन से बचने के लिए एक खास सीमा से नीचे के आकार में बने रहने की संभावना अधिक रहती है। यही वजह है कि फैक्टरियों के वितरण में असमानता आई है।

उद्योगों का सालाना सर्वे वर्षों से इसका उदाहरण बनता रहा है। सर्वे के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम देश की कुल फैक्टरियों में 96 फीसदी के हिस्सेदार हैं और 10 से कम कर्मचारियों वाले सूक्ष्म उपक्रमों की हिस्सेदारी इनमें 99 फीसदी है। 2,000 से अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों की संख्या इसमें बहुत कम है। आर्थिकी अरविंद सुब्रमण्यम एवं अन्य का विश्लेषण दिखाता है कि समस्या उद्योगों के सालाना सर्वे के आंकड़ों से कहीं अधिक बुरी है। एएसआई ने बड़ी फैक्टरियों की संख्या को बढ़ाचढ़ाकर पेश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई कंपनियां एक ही राज्य में अलग-अलग उत्पादन इकाइयां तैयार करती हैं। इससे न केवल एक ही कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियों की फैक्टरियां अलग-अलग होती हैं लेकिन सर्वेक्षण में इन्हें एक फैक्टरी के रूप में दर्शाया जा सकता है जिससे डेटा में गड़बड़ी होती है। लेखकों के मुताबिक इन विविध संयंत्रों की मौजूदगी देश के विनिर्माण संयंत्रों वास्तविक आकार से बड़ा आकार प्रदान करती है। बड़े संयंत्र कई वजहों से उत्पादक साबित होते हैं। लेखकों का अनुमान है कि विविध संयंत्रों की उत्पादकता एकल संयंत्र से करीब पांच फीसदी कम होती है। अधिकांश श्रम आधारित क्षेत्रों में मौजूद कम मार्जिन को देखते हुए उत्पादकता में पांच फीसदी का अंतर बहुत अधिक साबित हो सकता है। छोटे संयंत्रों के साथ और दिक्कतें हैं जिनकी विस्तार से जांच परख करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बड़े संयंत्र वैश्विक फैशन ब्रांडों से जुड़े बड़े ऑर्डर ले सकते हैं। बड़े संयंत्र में पूंजी निवेश अधिक उत्पादक साबित हो सकता है और ये मूल्य श्रृंखला में तेजी से ऊपर जा सकते हैं। कंपनियों का बहु-ब्रांड बनाने का चयन नियामकीय और राजनीतिक जोखिमों से जुड़ा हुआ है जो उन्हें छोटे आकार में बनाए रखते हैं। छोटे संयंत्र कठिन श्रम कानून व्यवस्थाओं से जूझ रही कंपनियों को अधिक लचीलापन मुहैया कराती हैं। अन्य सामान्य राजनीतिक जोखिमों मसलन दुर्घटना की वजह से कंपनियों को अधिक संयंत्र स्थापित करके बचा जा सकता है।

बांग्लादेश में हिन्दूओं पर अत्याचार, सख्त कार्रवाई की दरकार

बांग्लादेश की आबादी में 7.95 फीसदी-सवा करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो कुचक्र रचे गये, उसी तरह की साजिश बांग्लादेश में सिर उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू समुदाय पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। आज बांग्लादेश सांप्रदायिकता एवं कट्टरता की आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोराहे पर खड़े बांग्लादेश में यह खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए वहां अंतरिम सरकार ने हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक संस्थान पर हमलों की जानकारी देने के लिए हॉटलाइन शुरू की थी, लेकिन कितनी ही शिकायतें मिलने के बावजूद उन पर कार्रवाई का न होना, इनको लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार का चुप्पी साधे रखना इस समस्या को गंभीर बना रहा है।

ललित गर्ग

बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों एवं हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, मशहूर जेशोश्वरी मंदिर में मुकुट का चोरी होना, हिन्दू अल्पसंख्यकों के जबरन इस्तीफा के लिये दबाव बनाने की घटनाएं, दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमले चिन्ता के बड़े कारण हैं, यह हिन्दू अस्तित्व एवं अस्मिता को कुचलने की साजिश एवं षड़यंत्र है, जिस पर भारत सरकार को गंभीर होने के साथ इन पर नियंत्रण की ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है। बीते अगस्त में शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से हटना और भारत आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों द्वारा हवा दिया जाना शर्मनाक एवं विडम्बनापूर्ण है। नई दिल्ली में बांग्लादेश के हिन्दू-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बार-बार चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन करारा एवं सख्त संदेश देने की कोई कोशिश होती हुई नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा सरकार के शासन में यदि ऐसी घटनाओं पर सख्ती नहीं बरती गयी तो फिर कब बरती जायेगी? यह विडंबना ही है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व कार्यवाहक रूप में सरकार के मुखिया का दायित्व निभा रहे मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हिन्दुओं एवं हिंदू पहचान के प्रतीकों को निशाना बनाया जाना बदस्तूर जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी पर्व पर आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए हिन्दुओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर बड़ा संदेश दिया है, अपेक्षा है सरकार भी जैसे को तैसे वाली स्थिति में आकर हिन्दुओं की रक्षा की सार्थक एवं प्रभावी पहल करें। बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इन हमलों एवं कट्टरतावादी शक्तियों का सक्रिय होना भारत एवं बांग्लादेश दोनों ही देशों के लिये खतरनाक है। कट्टरपंथियों के निरंकुश बने रहने से वहां की सरकार के इरादे और इच्छाशक्ति सवालों के घेरे में है।

भारत ने उचित तरीकों से ही इन घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए इन पर न केवल चिंता जतायी बल्कि अपनी आपत्ति भी दर्ज करायी। गौर करने की बात है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का यह मसला थोड़े-थोड़े दोनों देशों के रिश्तों में खटास घोलते हुए एक अहम फैक्टर बनता जा रहा है। दुर्गापूजा के पंडाल में बम फेंके जाने की खबर स्वाभाविक ही बांग्लादेशी हिंदू बिरादरी को सहमा एवं डरा देने वाली है। जेशोश्वरी मंदिर में मां काली के ताज की चोरी इस मायने में भी अहम है कि यह ताज 2021 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे के तौर पर दिया था। यही नहीं, गुरुवार को चटगांव में दुर्गापूजा के दौरान कुछ दोषियों द्वारा जबरन इस्लामी झंडे के गीत गाए जाने की भी खबर आई। ऐसे में भारत अगर इन घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका जता रहा है तो उसे निराधार नहीं कहा जा सकता। ऐसे में लगातार बिगड़ती स्थितियों में यूनुस और उनके सहयोगियों को शासन और कट्टरीति से जुड़े गंभीर मसलों पर परिपक्वता दिखानी होगी। आंदोलन से जुड़े गैर जिम्मेदार तत्व अनाप-शनाप आरोप लगाएं तो कुछ हद तक समझा जा सकता है लेकिन अगर शासन में बैठे लोग भी इन तत्वों का समर्थन करते हुए दिखें तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। यह एक अराजकता की स्थिति है। बांग्लादेश में बद से बदतर हो रहे हालात एवं हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, हमलों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावधान कर कोई गलत नहीं किया। सकिय, व्यवस्थित और संगठित होकर ही ऐसी नापाक एवं संकीर्ण मानसिकताओं का माकूल जवाब दिया जा सकता है। भागवत ने कहा, ''दुर्बल रहना अपराध है, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। अगर आप संगठित नहीं रहते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।'' देश के दुश्मनों की ओर इशारा करते हुए मोहन भागवत ने कहा, ''भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी राह में अड़ंगा लगाने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए दूसरे देशों की सरकारों को कमजोर करना दुनिया में चलता रहता है।' लेकिन किसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिये हिंदुओं यानी अल्पसंख्यकों पर हमलों का सहारा लेना, उन्हें प्रोत्साहित करना विकृत एवं अराष्ट्रीय मानसिकता का द्योतक है। वैसे भी बांग्लादेश का विकास भारत के सहयोग पर निर्भर है, जिस भू-भाग को रवींद्रनाथ टैगोर 'आमार सोनार बांग्ला' (मेरा स्वर्णिम बंगाल) कहते थे, जहां की अर्थ-व्यवस्था एवं अन्य विकास योजनाएं भारत के सहयोग से ही आगे बढ़ती रही है, कभी भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को आंखें से ज्यादा बिजली भारत से मिलती है। अनाज की बड़ी खेप भारत से होती है। अगर भारत ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। बावजूद इन सब स्थितियों के वहां भारत-विरोधी घटनाओं का उग्र से उग्रतर होना खेद के पांव पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। बांग्लादेशी आकाओं को भागवान सद्बुद्धि दे। फिर भी अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो समय आ गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भारत कड़ा रुख अख्तियार करे। बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है। हिन्दू धर्म भारत की संस्कृति एवं आत्मा है। हिन्दू धर्म संस्कृति, त्याग और बलिदान का धर्म है। इसमें हमेशा दूसरे धर्मों को सम्मान देने का काम किया है।

हिन्दू धर्म उदारता, प्रेम, आपसी सद्भाव और सहनशीलता पर आधारित धर्म है। हिन्दू धर्म की सहिष्णुता को कमजोर मानकर हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार होता रहा है। वैसे तो प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, किन्तु विकृत मानसिकता वाले लोगों ने हिन्दू धर्म को मध्यकाल से ही नीचा दिखाने की कोशिशें की। भारत पर लगातार आक्रांताओं के हमले होते रहे और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। हिन्दुओं के लाखों मंदिर तोड़े गए। हिन्दुओं से अपने ही देश में हिन्दू होने पर 'जजिया' वसूल कर लगाया गया। पूर्व की सरकारों ने भी वोट की राजनीति के चलते हिन्दुओं को दोयम दर्जा पर रखा। फिर भी हिन्दू धर्म ने उदारता और सहनशीलता को नहीं छोड़ा। अगर हिन्दू कट्टर होता तो अन्य धर्मों के लोग भारत में नहीं दिखते। देश बंटवारे के समय पाकिस्तान में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिन्दू थे लेकिन आज उनकी आबादी 2 प्रतिशत भी नहीं रही और भारत में मुसलमानों की आबादी 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत नहीं होती। यह हिन्दू उदारता का ही परिणाम है। लेकिन प्रश्न है कि आखिर कब तक हिन्दू ऐसी अग्नि परीक्षा देता रहेगा? कब तक हिन्दू की सहिष्णुता को कमजोरी मानकर उन पर अत्याचार होते रहेंगे? कब तक हिन्दू शक्तिस्वरूप होकर भी निर्बल बना रहेगा? इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे वर्ना हिन्दुओं को अस्तित्वहीन करने की कोशिशें कामयाब होती रहेंगी।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक्रारों को पूरा करेंगे। यह आप एक अच्छा पार्टी है कि आपके लोकल के ऐसे साथियों होंगे है, जब आपको किसी कुशल होगी और दूसरी ओर, आपको दिल बातों में लापरवाह तथा दयालु। तब तो किसी सच्चे दोस्त में और अधिक खुशी को दुगुनाने तथा स्वास्थ्यवक्त अनेक नये लाभ के संकेत मिलेंगे, विशेष परिस्थितियां तलाशें हों तो, जब तक लापरवाहता हो सके संयम और बातचीत से तथा पढ़ता करेंगे

मेष

स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और खेलीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

वृष

आज वाणी पर संयम रखें, खेलीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आप की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मिथुन

किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कर्क

सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह

व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कन्या

दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

तुला

मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित न हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक

मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

धनु

अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मकर

आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और सांस्कृतिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

कुंभ

आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

मीन

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में इगोइज्म का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। उपेक्षित और अधिक व्यवसायिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। खेलीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी दम्पति को जिन्होंने अपने जीवन दर्शन से अपनी पीढ़ी को मानवीय मूल्यों के बारे में ना केवल समझाया अपितु धर्म कर्म के इस जीवन पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। जी हां दुली चन्द जैन और उनकी धर्मपत्नी निर्मला जैन जीवन में कृतज्ञता के भाव के लिए संतुष्टि की परिभाषा को समझने का अर्थ क्या रहा और इसका प्रतिफल आखिर क्या मिलता है यदि ये दर्शन करने हैं तो इस परिवार के वट वृक्ष के रूप में छाया और शीतलता प्रदान कर रहे इस दम्पति को देख लीजिए। इन दोनों का सरकारी पेशा और मूलमन्त्र एक ही रहा। जीवन में प्राथमिकता के साथ समर्पित होकर कार्य करते रहने से ही सुपरिणाम हासिल हो सकते हैं। अलवर में 1949 में जन्मे श्री दुलीचन्द जैन लाला कश्मीरी लाल जी जैन के सबसे छोटे पुत्र हैं। सरोफ व्यवसायी लालाजी स्वयं नियमित धार्मिक दिनचर्या के धनी रहे और इसीका परिणाम हुआ कि उनके सभी बच्चे मंदिर सेए समाज से जीवन पर्यन्त जुड़े रहे। 11 भाईबहनों में सबसे छोटे दुलीचंद जी जैन ने 1971 में जोधपुर से भारतीय खाद्य निगम से अपनी जीवन यात्रा आरंभ की और 1976 में उनका विवाह श्रीमती निर्मला जैन से हुआ। ऊंचेखनीय है कि निर्मला जी भारतीय खाद्य निगम जयपुर में सेवारत थीं। आप दोनों ही अपने पूरे सेवाकाल में भारतीय खाद्य निगम में एक समान ही पोस्ट पर कार्यरत रहे और 2003 में आप दोनों ही ने एक साथ वी आरएस लिया। परिवारए समाज और धार्मिक क्षेत्र में आपके योगदान की बात करें तो यहां चलता है कि शांत रहकर भी कार्य कितने मजबूती से किये जा सकते हैं।

दुली चन्द जैन दंपति (सेवानिवृत्त अधिकारी)

महावीर जिनालय (जैन मंदिर काला कुआँ) का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने से पूर्ण कराने तक में आपकी भूमिका केंद्रीय रही। 1989 में काला कुआँ में लगभग 150 जैन परिवार निवासरत थे किंतु उस समय यहाँ जैन मंदिर नहीं था। चूंकि श्री दुली चंद जी जैन बचपन से ही मंदिरों से जुड़े रहे इसीलिए शीघ्र ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया और पिंक टीम में 4-5 लोगों ने घर घर जैन समाज के लोगों की सूची एकत्र कर समाज से सम्पर्क स्थापित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1992 को जिस मंदिर जी का शिलान्यास हुआ उसके 6 माह में ही 15 जनवरी 1993 को भव्य पंच.कल्याणक महोत्सव के साथ मंदिर जी का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही भगवान महावीर की खड्गासन प्रतिमा जी विराजमान हुई। इसी के साथ शैकड़ों जैन धर्मावलंबियों की नियमित मंदिर दर्शन की चर्या सुचारू हुई। श्री दुलीचन्द जैन का जीवन का मूलमंत्र है कि ' यदि हमें ये ज्ञात है कि सम्मानजनक जीवनयापन के लिए कितना अर्थोपार्जन आवश्यक है तो इससे संतुष्टि का भाव भी तभी जागृत होगा। तभी हम अपने अतिरिक्त अपने परिवार के साथ समाज के लिए भी अपना योगदान दे सकेंगे। इसी मूलमन्त्र को केंद्र में रखते आए हैं श्री दुलीचंद जैन और श्रीमती निर्मला जैन। क्लब बैंक हो, समाज का कोई भी कार्य हो, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा हो, ये तन-मन-धन से सक्रिय रहते आए हैं।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 को बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- प्रास और फ्रांस की सेनाओं के मध्य लड़ाई 1806 को आरंभ हुई। इससे एक दिन पहले नेपोलियन ने छह दिवसीय युद्ध में प्रॉस की सेना को पराजित किया था।
- नेपोलियन बोनापार्ट हार के बाद निर्वासित जीवन व्यतीत करने 1815 को सेंट हेलेना द्वीप पहुंचे।
- कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में 1866 को जबरदस्त आग लगने से 2500 मकान जलकर खाक।
- अलफ्रेड ड्रादफुस पर पेरिस में 1894 को मुकदमा आरंभ हुआ। वह यहूदी मूल का फ्रांसीसी अफसर था जिस पर चलाया जाने वाला मुकदमा 19वीं शताब्दी में फ्रांस की बहुचर्चित घटना बन गयी।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को 1917 में जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मारी।
- वर्ष का पांचवा उष्णकटिबंधीय तूफान लीवर्ड द्वीप के उत्तर में 1923 को आया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति कालिव्न कूलीद्ज ने 1924 में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया।
- टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत 1932 में की।
- टाटा एयरलाइन (जो कालांतर में एयर इंडिया बन गया) की पहली उड़ान 1935 भरी।
- त्रिपुरा राज्य को भारत में 1949 को सम्मिलित किया गया।
- मिस्र की संसद ने स्वेज नहर समझौते को 1951 में रद्द करने के फैसले पर मुहर लगाई।
- अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने 1958 में मिस्र के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।
- सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्श्चेव की सेवानिवृत्ति ने 1964 को पूरे विश्व को चौंका दिया।
- अनवर सदात मिस्र के राष्ट्रपति 1970 को चुने गए।
- सोवियत संघ ने 1978 में पूर्वी कजाखस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया।
- उज्वला पाटिल 1988 में पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी।
- सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
- फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश 1996 को बना।
- अरुंधति राय को 1997 में उनके उपन्यास 'द गॉड आफ स्माल थिंग्स' के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया।

विशेष आलेख

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम : एक व्यक्तित्व

एक बेहतरीन शिक्षक, एक पायलट, राइटर, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति जैसी तमाम उपलब्धियां हासिल करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने 2010 में वर्ल्ड स्टूडेंट्स-डे घोषित किया था। तब से हर साल 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से भी जरूरी चीज है हौसला, हौसला आपकी सोच को वह उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां पढ़ी होंगी लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। जैनुलाब्दीन और आशीयम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में कलाम का जन्म हुआ था। डॉ.कलाम का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। हालांकि भारत की नई पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्वरूप हैं। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। जिसके लिए उन्होंने कहा कि ध्यापके सपने के सच हो सकने के पहले आपको सपना देखना है ५। एक वैमानिकी इंजीनियर होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए जहाज में उनकी विशाल इच्छा ने उन्हें सक्षम बनाया। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को नहीं रोका। डॉक्टर कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान में ग्रेजुएशन एवं मद्रास इंस्टिट्यूट से वैमानिकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वे एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वीं राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 तक देश की सेवा की। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे क्योंकि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसरो के लिए दिया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उनके द्वारा नेतृत्व किया गया जैसे रोहिणी.1 का लॉन्चर प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंटए मिसाइलों का विकास अग्नि और पृथ्वी आदि। भारत की परमाणु शक्ति को सुधारने में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अपने समर्पित कार्यों के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। कलाम साहब ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबें आज भी लोगों और युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है जैसे-

- 'इंडिया 2020रू ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम ।
- 'विंग्स ऑफ फायर एनऑटो बायोग्राफी ।
- 'इग्नाइटेड माईंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया ।
- 'द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर्स ।
- 'गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द परपज ऑफ लाइफ ।
- 'मिशन ऑफइंडिया विजन ऑफइंडियन यूथ ।
- 'इंडियारिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज ।
- 'यू आर योर्न टी एलीम टेक माय जर्नी बियोंड ।
- 'द साइंटिफिक इंडियन फ्यर्ट सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस ।
- 'फैलियर टू सक्सेसः लीजेंडरी लाइव ।

वह हमेशा कहते थे कि लिखना मेरा प्यार है अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं। आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूं, आमतौर पर मध्य रात्रि में शुरू करता हूं, कभी-कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू कर दूं। वे दुरदर्शिता पूर्ण विचारों से युक्त व्यक्ति थे। जिन्होंने हमेशा देश के विकास का लक्ष्य देखा। भारत-2020 के शीर्षक की अपनी किताब में उन्होंने देश के विकास के बारे में कार्य योजना की स्पष्ट किया। उनके अनुसार देश की असली संपत्ति युवा है। इसी वजह से वह हमेशा उन को प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे हैं। वह कहते थे कि राष्ट्र को नेतृत्व में आदर्श की जरूरत है जो युवाओं को प्रेरित कर सके। डॉ कलाम ने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम से युवाओं के लिए एक मिशन की शुरुआत की। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक उपलब्धियों और अन्य मेधावी कार्यों के अलावा बच्चों के बीच अपने प्यार तथा स्नेह के लिए भी जाने जाते थे। वे बच्चों की आंखों का तारा थे। उच्च विचार व सादा जीवन शैली से डॉक्टर कलाम ने हमारे राष्ट्र को जो मजबूती दिलाई उसका कोई सानी नहीं है वह भारत के सच्चे सपूत थे। साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने देश का सर्वोच्च पद ही हासिल नहीं किया बल्कि वैज्ञानिक बनकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। ऐसे लोग धरती पर कभी कभार ही जन्म लेते हैं। ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के लोकप्रिय के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग के आई आई एम में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया था। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे।

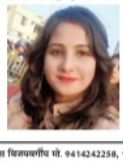

विजयलक्ष्मी व्याख्याता (इतिहास) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडली सैयद, अलवर

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इंडीपेंडेंट सेक्टर खण्डावा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-लायक विजयवर्गीय फो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन न.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पोलाश सिंह का जोहड़, अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

अनुशासन की चिंता

कोई भी समाज संयम, सहिष्णुता और सद्भावना से ही सशक्त होता है। अगर कभी समाज इन लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रतिकूल चलने लगता है, तो न केवल हिंसा की आशंका बढ़ जाती है, बल्कि समाज में भय का माहौल बन जाता है। वाकई संयम का ही अभाव था कि दिल्ली में सड़क पर रास्ता देने-न देने का एक मामला फिर जानलेवा हो गया। दशहरा मेले से लौट रहे दो भाइयों पर तीन अपराधियों ने ऐसे हमला बोल दिया कि एक भाई की मौत हो गई। क्या सड़क पर हुए इस विवाद को सद्भावना के साथ सुलझाया जा सकता था? क्या हम सड़क पर या समाज में संयम खोने लगे हैं? क्या हमारे मन में नाना प्रकार की कुंठाएं भरती चली जा रही हैं? क्या परस्पर ईर्ष्या ने हमें क्रोधी बना दिया है? ये कटु सवाल पर गौर करने की जरूरत है, पहले के दौर में अक्सर लोग कहते थे कि सहना सीखो, मिल-जुलकर रहना सीखो। गांधीजी के हवाले से भी अक्सर कहा जाता था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा आगे कर दो। अब जब शांति-अहिंसा के दर्शन को भुलाया जा रहा है, तब सड़क हो या समाज, लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने को लालायित हैं।

प्रतिमा विसर्जन के समय उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हुआ या झारखंड के गढ़वा में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद हर समुदाय यह मानने लगा है कि पूरे समाज या देश को उसके हिसाब से चलना चाहिए, अगर देश या समाज उसके हिसाब से नहीं चलेगा, तो वे कानून हाथ में ले लेंगे। किसी शोभायात्रा पर पत्थर फेंकने की घटना सामान्य नहीं है, ध्यान दीजिए, नफरत के ये पत्थर कोई एक दिन में जमा नहीं हुए हैं। कई लोग बदला लेने या अपनी मनमानी चलाने के लिए भरे बैठे हैं, उन्हें कोई भी बार-बार यह नहीं दिला रहा है कि सद्भाव के साथ रहना ही समझदारी है। ऐसे लोग जगह-जगह हैं, तभी तो शोभायात्राओं पर जगह-जगह हमले हुए हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, शोभायात्रा निकालने की अपनी शोभा है। शोभनीय ढंग से अगर ऐसा किया जाए, तो शायद ज्यादा समस्या नहीं होगी। उग्रता, हुड़दंग, अभद्र शोर, भड़काऊ नारेबाजी से क्या किसी यात्रा की शोभा बढ़ सकती है? हां, अगर कोई शोभनीय और आधिकारिक रूप से स्वीकार्य यात्रा पर आपत्ति करता है, तो यह किसी अपराध से कम नहीं है। धार्मिक आचरण की आदर्श स्थिति है कि आपके व्यवहार से किसी को तकलीफ न होने पाए। तकलीफ पहुंचाना अधर्म है।

किसी भी शोभायात्रा पर पत्थर फेंकने की घटना सामान्य नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारे समुदायों में नफरत के ये पत्थर कोई एक दिन में जमा नहीं हुए हैं।

वैसे, ईमानदारी से यह भी देखना चाहिए कि लोग संयम, सहिष्णुता त्यागकर आखिर क्यों कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं? किसी यात्रा का अशोभनीय होना और किसी शोभा यात्रा को निशाना बनाया जाना, दोनों ही स्थितियों में कानून-व्यवस्था की कमी जिम्मेदार होती है। पुलिस को ऐसी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हर समुदाय में शासन-प्रशासन की मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब यह भी है कि वहां के जन-प्रतिनिधि भी समाज में पलते विवादों को सुलझाने में नाकाम हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में शांति बनाए रखना प्राथमिक रूप से पुलिस और जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। सामाजिक, धार्मिक संगठनों को भी समाज में उग्रता बढ़ाने के काम करने के बजाय विनम्रता को खाद-पानी देना चाहिए। समाज में चहुंओर बढ़ते गुस्से का यही समाधान है।

बदलाव की ओर कदम बढ़ाता बस्तर

राय की राय

यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

चार दशक लग गए माओवादियों को यह समझने में कि अब राज्य इतना मजबूत हो गया है कि किसी एक कोने में सशस्त्र संघर्ष से उसे उखाड़ना तो दूर, हिलाया भी नहीं जा सकता।

बस्तर में बाजार पहुंच गया है। बाजार तो पहुंचता ही पर माओवादियों ने इस प्रक्रिया को थोड़ा विलंबित कर दिया था। अब जब सशस्त्र संघर्ष के जरिये राज्य मशीनरी पर कब्जा करने का सपना अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इस आंदोलन के धुर विरोधी भी मानते हैं कि यदि आदिवासियों ने हथियार न उठाए होते, तो इस बात की पूरी आशंका थी कि राज्य ने उन्हें हाड़-मांस का पुतला न समझकर सिर्फ संग्रहालयों में सजाकर रखने वाली चीज समझा होता। सुदूर जंगलों और पर्वतों पर फैले इनके गांवों को सड़कों, बिजली, स्कूलों या अस्पतालों की भी जरूरत हो सकती है, यह समझने में भारतीय राज्य को काफी समय लगा।

पिछले एक हफ्ते से मैं पुराने बस्तर जिले में घूम रहा हूं। पिछले कुछ समय में यह सात जिलों में बंट चुका है। मुझे याद आता है, अपने छात्र जीवन का बस्तर, जो सैकड़ों मील दूर रहने वाले मुझ जैसों के लिए हकीकत से अधिक फसाना होता था। किसी शहरी के लिए आदिवासी एक खास तरह की रोमांटिक और सपनीली दुनिया के अंग होते थे। उन दिनों की लोकप्रिय पत्रिकाओं *धर्मयुग* और *साप्ताहिक हिन्दुस्तान* में हम नृत्य करते और चाचल की शराब पीकर झूमते आदिवासियों को किसी दूसरे लोक का प्राणी समझते। विवाह पूर्व रिश्तों से जुड़ी उनकी स्वीकृति 'घोटुल' हमें किसी कल्पना-लोक की चीज लगती थी। ऐसा लगता कि रात भर नाचते-गाते, ढोल-नगाड़ा बजाते और जंगलों में प्रकृति के सान्निध्य में खिलखिलाते वनवासियों के जीवन में कोई दुख नहीं है। वह तो अपने एक सहपाठी से पहली बार पता चला कि पत्रिकाओं के रंगीन पृष्ठों पर पसरी हंसती खिलखिलाती तस्वीरों वाले आदिवासियों के पीछे खड़े पहाड़ दुखों के हैं। जिन जंगलों में वे रहते हैं, उन पर कब्जा हत्याएं और बलात्कारियों का है।

मेरे उस सहपाठी के पर-बाबा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रोजी-रोटी की तलाश में निकलकर आज के बीजापुर जिले के जंगलों में छिपे किसी दुर्गम पहाड़ी गांव में बिला गए। वर्षों बाद जब वह एक सुबह अपने गांव में प्रकट हुए, तो उनकी गठरी-मोठरी में ग्रामीणों को चकित कर सकने वाली संपदा थी, जो उन दिनों के चलन के मुताबिक अलग-अलग अंगों पर चढ़े वस्त्रों में सावधानी से सिली हुई थी। इनके अलावा उनके पास कहानियों के खजाने थे, जो अलग-अलग वय के लोगों के लिए अलग रंगों की दुनिया लिए हुए थीं। मसलन, बच्चों को यह रहस्य बड़ा मनोरंजक लगता कि आदिवासी इतने 'भोले' थे कि एक मुट्ठी नमक के बदले वे उनसे लड़ी (बैलगाड़ी) भर चिरौंजी, इमली, शहद, लाख या तेंदू पत्ते ले लेते थे। कस्बों में मंडियां थीं, जहां तक वे माल पहुंचाते और फिर वहां से आढ़तिए उसे विशाखापत्तन या रायपुर ले जाते। बच्चों को दूर हटाकर वे अपने हमउम्रों को आंखें मटका-मटकाकर उन औरतों के बारे में बताते थे, जो पुलिस, जंगलात या राजस्व कर्मचारियों के साथ जबरिया या चुटकी भर नमक के बदले सोने के लिए अभिशप्त थीं। सहपाठी की बातें सुनकर पता चला कि तस्वीरों में मुस्कराते चेहरों के पीछे दुखों के पहाड़ थे। इस दुख से निजात की पहली कोशिश एक राजा ने की। उड़ीसा (अब ओडिशा) के किसी राज परिवार के वंशज को जगदलपुर का राजपाट मिला। उसी शृंखला के अंतिम राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने, जिन्हें आदिवासी देवता मानकर पूजते थे, उन्हें संगठित करने की कोशिश की, पर वे भारतीय राज्य की संप्रभुता को चुनौती देते हुए 1966 की एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए।

आदिवासियों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के सबसे गंभीर और निर्णायक प्रयास उस सशस्त्र आंदोलन के जरिये हुए, जो पश्चिम बंगाल में 1970 के दशक में नक्सलबाड़ी नामक एक छोटे से कस्बे से शुरू हुआ था। बंगाल में तो यह आंदोलन दो दशकों में खत्म हो गया, पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुराने मध्य प्रदेश और मौजूदा छत्तीसगढ़ के संधिस्थल पर अब भी हिचकियां ले रहा है। शुरुआती दौर में नक्सल नाम से चर्चित इस आंदोलन को बंगाल के बाहर माओवाद कहा गया। छत्तीसगढ़ का पूरा बस्तर प्रखंड इस आग में झुलसा और चार दशक लग गए माओवादियों को यह समझने में कि अब राज्य इतनी मजबूत संस्था में तब्दील हो गया है कि किसी एक कोने में सशस्त्र संघर्ष से उसे उखाड़ना तो दूर, हिलाया भी नहीं जा सकता। आज जब मैं वर्षों के अंतराल पर बस्तर के गांवों-कस्बों में घूम रहा हूं, तो स्पष्ट दिख रहा है कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर जैसे इलाकों में आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले साल भर में ढेड़ सौ से अधिक माओवादी लड़ाके पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में भी सड़कें और संचार के आधुनिकतम उपकरण पहुंच गए हैं, जो सुरक्षा बलों को बढ़त दे रहे हैं।

सरकारों की भी समझ में आ गया है कि आदिवासियों को सड़क, अस्पताल और विद्यालय की जरूरत है। सशस्त्र आंदोलन के चलते पुलिस, जंगलात और राजस्व कर्मियों की ज्यादतियों पर कुछ अंकुश लगा। तेंदू पत्ते का संग्रहण करने वाले ठेकेदारों को उनकी मजदूरी बढ़ानी पड़ी। यह सब हुआ, पर बड़ी कीमत चुकाने के बाद। माओवादियों और सुरक्षाकर्मियों, दोनों ने सैकड़ों जानें गंवाईं।

मैं लगातार इस इलाके में घूम रहा हूं और दिलचस्पी से उन परिवर्तनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो माओवाद और फिर उसके खात्मे के बाद इस इलाके में घट रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ जाने के बाद स्वाभाविक था कि बाजार का यहां प्रवेश हुआ। मैंने इसके सकारात्मक पहलू को हर जगह अनुभव किया। चाहे वह नया रायपुर में बस रही राजधानी का बड़ा सरोवर हो या चिऊकोट का जलप्रपात, हर जगह रेहड़ी वाले स्थानीय लोग हैं और लगभग सभी क्षुधा कोड के जंगिरी आंचलिक व्यंजन *जोर से बोलो, तुम भी बोलो, सारे बोलो जय माता दी*, के पंजाबी जयकारे लगा रहे थे। वर्दी पहने ज्यादातर पुलिसकर्मी आदिवासी लग रहे थे और मेरी अनुभवी आंखें भांप सकती थीं कि उनका व्यवहार जनता के साथ रूखा तो नहीं ही था।

एक अंतिम बात- बाजार अभी तक आदिवासियों की निश्छल हंसी को प्रभावित नहीं कर सका था और हम संपर्क के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे थे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पाकिस्तान जाने का भारतीय फैसला कितना कारगर

यहां स्कैन करें

शरत सभरवाल | पूर्व भारतीय उच्चायुक्त, पाकिस्तान

भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सदस्य देश है। चूंकि इस संगठन के सदस्यों का विस्तार यूरेशिया के बड़े भूभाग तक है, इसलिए इसकी बैठकों में होने वाली चर्चा नई दिल्ली के लिए काफी अहमियत रखती है। इसी कारण भारत को इसमें नियमित तौर पर शामिल होना चाहिए। मगर यह तर्क तब बेमानी हो जाता है, जब इसकी बैठक पाकिस्तान में होने वाली हो, जैसा कि अभी 15 और 16 अक्तूबर को इसके शासनाध्यक्षों की बैठक आयोजित है। आखिरकार, अगस्त 2016 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दक्षेस के गृह/ आंतरिक मामलों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद कोई भी वरिष्ठ भारतीय नेता पाकिस्तान नहीं गया है।

बहरहाल, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होने इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। इससे यह कयास भी गति पकड़ने लगा है कि क्या बैठक से इतर कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी? अगर ऐसा कुछ होता है, तो अहम सवाल यही है कि क्या इससे आपसी रिश्तों में कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान किसी भी द्विपक्षीय बैठक के लिए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली की मांग पर अड़ा हुआ है और पाकिस्तानी हुकूमत भारत विरोधी बयानबाजी मुसलसल किए जा रही है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण भी उनकी सदनीयत का संकेत नहीं देता।

विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इससे यह कयासबाजी गति पकड़ने लगी कि क्या कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी?

दरअसल, इस्लामाबाद आंतरिक मुश्किलों में इस कदर उलझा हुआ है कि उसके लिए विदेश नीति के मोर्चे पर कोई बड़ी पहल करना मुश्किल है। दिवालिया होने के कगार पर खड़ी उसकी अर्थव्यवस्था को अभी मुद्रा कोष से सात अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज से कुछ राहत मिली है। फिर, वहां राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। ऐसे में, भारतीय विदेश मंत्री की इस यात्रा से द्विपक्षीय मोर्चे पर सकारात्मक विकास की उम्मीद काफी कम है। हालांकि, यह अच्छा है कि नई दिल्ली ने अपने मंत्री को भेजने का फैसला करके अपने लचीले रुख का संकेत दिया है। इससे पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठानों की सार्वजनिक बयानबाजी के पीछे की मंशा को समझने का मौका मिल सकता है।

खैर, आपसी बातचीत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, पश्चिमी सीमा पर पसरी अपेक्षाकृत शांति के कारण भारत को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी आशंका है कि पाकिस्तान अपने मौजूदा संकट से ज्यों ही उबरेगा, भारत को सीमा पार के दुस्साहसों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, वह कयास भी अगर साकार हुआ कि पाकिस्तान टूट जाएगा, तो भारतीय सीमा पर उथल-पुथल बढ़ सकती है। इसीलिए, हमारे लिए पाकिस्तान एक ऐसी चुनौती है, जिससे कूटनीति सहित तमाम साधनों से हमें निपटना होगा। दूसरी, पिछले कुछ वर्षों से भारत पाकिस्तान के बजाय चीन को मुख्य खतरा मानने लगा है। ऐसा पश्चिमी सीमा पर शांति के कारण हुआ है। इसकी अनिवार्यताओं और बढ़ती आंतरिक चुनौतियों के मद्देनजर हालात संभालने की पाकिस्तानी महत्वाकांक्षा की वजह से ही 2021 में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष-विराम लागू हुआ था। यह एक संकेत था कि आपसी रिश्तों को पूरी तरह से सामान्य बनाना बेशक मुश्किल हो, पर द्विपक्षीय संबंध अस्थिरता को कम कर सकता है। इसे नजरंदाज नहीं करना चाहिए।

तीसरी, उथल-पुथल के लंबे दौर के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना भरोसा जताया है। यहां के दल शांति-स्थापना के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत का आह्वान करते रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति में संविधानिक बदलाव का विरोध किया है। उसकी विघटनात्मक कार्रवाइयां वहां के हालात पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। ऐसे में, नई दिल्ली के पास अभी दो विकल्प हैं। पहला, पाकिस्तान पर दबाव बरस्तूर बनाए रखना, मगर इससे पश्चिमी सीमा पर उथल-पुथल बढ़ सकती है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिये जवाबी दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, द्विपक्षीय कूटनीति के जरिये पश्चिमी सीमा पर स्थिरता बढ़ाने के अवसरों के मद्देनजर संतुलित नजरिया बनाए रखना। इस संदर्भ में हमें विदेश मंत्री का हालिया बातों गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी सकारात्मक कदम का भारत स्वागत ही करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

किसी को नाम क्या देना

हम किसी भी चीज को नाम क्यों देते हैं? किसी फूल, व्यक्ति, भावना आदि पर हम कोई लेबल क्यों लगा देते हैं? हम ऐसा अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने, उस फूल का बखान करने आदि के लिए करते हैं या फिर उस भावना से अपना तादात्म्य बिठाने के लिए। हम किसी चीज को, गुलाब के फूल को कोई संज्ञा इसलिए देते हैं, ताकि दूसरों को बता सकें; या फिर उसे नाम देकर हम सोचते हैं कि हमने उसे समझ लिया है; हमने उसका वर्गीकरण कर लिया है और ऐसा करके हमने उस फूल की समस्त अंतर्वस्तु व सौंदर्य को जान लिया है।

किसी वस्तु को एक संज्ञा देकर हम उसे एक कोटि में रख देते हैं और हम उसे और ध्यान से नहीं देखते। लेकिन यदि हम उसे कोई नाम नहीं देते, तो हमें उसे देखना पड़ता है; तात्पर्य यह कि तब हम किसी फूल या वस्तु को एक नएपन के साथ, परख की एक नवीन मौलिकता के साथ देखते हैं; हम उसे ऐसे देखते हैं, मानो पहले उसे कभी न देखा हो। नाम देना व्यक्तियों या वस्तुओं को निपटा देने का बड़ा आसान तरीका है- वे जर्मन हैं, जापानी हैं, अमेरिकी हैं, हिंदू हैं, ऐसा कहकर आप उन्हें एक लेबल बना सकते हैं और फिर उस लेबल को नष्ट कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों को आप कोई लेबल न दें, तो आप उन्हें देखने पर मजबूर होंगे और तब किसी की हत्या करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा।

आप किसी लेबल को नष्ट कर सकते हैं और खुद को बड़ा धर्मात्मा समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई लेबल, कोई कोटि न दें और उस वस्तु विशेष को सीधे-सीधे देखें, वह चाहे कोई मनुष्य हो, फूल हो, कोई प्रसंग हो या कोई भावना, तब आप उसके साथ अपने संबंध पर गौर किए बिना नहीं रह सकेंगे। अतः नाम या लेबल देना किसी चीज से पीछा छुड़ाने, उसके निषेध, उसकी निंदा-प्रशंसा की एक बड़ी सुविधाजनक विधि है। यह इसका एक पक्ष हुआ।

कभी आपने सोचा है कि हमेशा नामकरण करने वाला, चुनने वाला, लेबल देने वाला वह केंद्र कौन सा है? हम सभी महसूस करते हैं कि ऐसा कोई केंद्र, कोई मर्म तो है, जहां से हम कर्म कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। क्या है वह केंद्र, वह स्रोत? कुछ लोग ऐसा सोचना पसंद करेंगे कि वह एक आध्यात्मिक तत्व है, ईश्वर है या ऐसा ही कुछ है। अतः हमें यह जानना चाहिए कि वह मर्म, वह केंद्र क्या है, जो नाम दे रहा है, शब्द दे रहा है, मूल्यांकन कर रहा है? निस्संदेह, वह केंद्र है स्मृति। वह संवेदनाओं की एक शृंखला है, जिनके साथ तादात्म्य कर लिया गया है और जिनके घेरे बना दिए गए हैं, वर्तमान के माध्यम से जीवन पाता अतीत। और इस केंद्र के विसर्जित होने पर ही बोध संभव होता है।

किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना को नाम या लेबल देना उससे पीछा छुड़ाने की, उसके निषेध की और उसकी निंदा-प्रशंसा की एक बड़ी सुविधाजनक विधि है।

जे कृष्णमूर्ति

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्मों ने भारतीय मध्यम वर्ग को ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे पास ऐसे बहुत से भारतीय हैं, जो कम ब्याज वाली जमा योजनाओं में निवेश करने के बजाय जोखिम लेने और बाजार में उतरने के इच्छुक हैं।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 15 अक्टूबर, 1949

भारत की वाणी

अमरीकी प्रजातन्त्र के प्रतिनिधियों ने पहली दफा पं. जवाहरलाल नेहरू के मुख से भारत की वाणी को सुना। भारत की भावनाओं और आकांक्षाओं को आज पं. नेहरू के अलावा और कोई अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता। गांधीजी भारत की कोटि-कोटि जनता के एकमात्र वक्ता थे, उनके बाद नेहरूजी को ही वह दुर्लभ दर्जा मिला है। नेहरूजी ने अमरीकी प्रतिनिधियों को बताया कि भारत की जिस वाणी को उन्होंने सुना, वह उनके लिए नई नहीं है, बल्कि उसे वह अपने महापुरुषों के मुख से पहले भी सुन चुके हैं। उन्होंने कहा, 'वह यूरोप की पुरानी दुनिया की वाणी नहीं है, बल्कि एशिया की उससे भी पुरानी दुनिया की वाणी है। वह प्राचीन सभ्यता की वाणी है- विशिष्ट और सजीव, किन्तु उसने आधुनिक दुनिया से भी बहुत कुछ सीखा है। यह पुरानी भी है और नई भी।' अमरीकी प्रतिनिधियों को नेहरूजी को सुन लेने के बाद यह प्रतीत हो गया होगा कि आज का भारत केवल अध्यात्म और आदर्श के स्वप्न लोक में विचरण नहीं करता, बल्कि जीवन के यथार्थ तथ्यों का सामना करने को भी कटिबद्ध है।

नेहरूजी ने भारतीय क्रान्ति के स्वरूप को अमरीकी प्रतिनिधियों के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस सिलसिले में वह भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख किये बिना कैसे रह सकते थे? उन्होंने उस नये तरीके का जिक्र किया, जिसके जरिये भारत ने अपनी खोयी आजादी को पुनः प्राप्त किया और जिसकी बदौलत जो कल दुश्मन थे, वही आज मित्र बन गये हैं। नेहरूजी ने कहा, हमको आक्रमण का सामना करना होगा, उसका प्रतिरोध करना होगा, किन्तु हम घृणा अथवा भय से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि शांति और समझौते का अन्तिम लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखेंगे। दुनिया को आज जिन उलझनों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका हल तभी संभव है, जब दुनिया के राष्ट्र गांधीजी द्वारा बताये सत्य और शांति के मार्ग को अपनायें और अपने कार्यों और विचारों को नैतिक सिद्धांतों से विलग न होने दें। भारत का मार्ग यही सत्य और शांति का मार्ग होगा। किन्तु नेहरूजी ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि मानवी स्वतन्त्रता को चुनौती दी जायेगी, तो भारत उस अवस्था में चुप न बैठेगा।

राष्ट्र की प्रगति को गति मिल रही

भारत में बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने और कनेक्टिविटी बढ़ाने में पीएम गति शक्ति योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके तहत न सिर्फ विभिन्न मंत्रालयों की सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं, बल्कि मंत्रालयों में आपसी समन्वय से उनका क्रियान्वयन भी अच्छे से हो रहा है। करीब तीन वर्ष पहले 15 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी और उसी साल अक्तूबर में इसके मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया था। इसका उद्देश्य यही था कि सभी आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। अच्छी बात है कि अपने उद्देश्य में यह योजना लगातार आगे बढ़ रही है।

यह देश के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने वाली परिवर्तनकारी पहल है। अच्छी बात यह है कि नेशनल मास्टर प्लान का फायदा अब निजी कंपनियों को भी मिलने के दावे किए गए हैं। अभी तक वह योजना सिर्फ सरकारी विभागों और एजेंसियों तक सीमित रही है। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, जल मार्गों और हवाई अड्डों के विकास के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये की लागत से 200 से भी अधिक परियोजनाओं की सिफारिश की जा चुकी है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि मास्टर प्लान के तहत उन्हीं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिनकी लागत पांच सौ करोड़ रुपये या इससे ज्यादा हो। दरअसल, यह योजना जिन छह स्तंभों पर टिकी है, वही इसकी ताकत है। ये छह स्तंभ हैं- व्यापकता, प्राथमिकता, निर्बाध, अनुकूलन, तालमेल, विश्लेषण और गतिशीलता। चूंकि मंत्रालयों व विभागों की नियोजित पहल की जानकारी एक-दूसरे को होती है, इसलिए व्यापक तरीके से योजना बनाने और उन पर काम करने में मदद मिलती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना बताता है कि अनुसूचित परियोजनाओं में अधिकतम संख्या सड़क 101, रेलवे 73, शहरी विकास 12 और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित चार परियोजनाएं हैं।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क या भूमि बंदरगाह और उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की ढांचागत योजनाओं को शामिल किया गया है। बुनियादी ढांचे का उन्नत होना कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे तमाम देशों को देखकर लगाया जा सकता है। इन सभी देशों ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जबर्दस्त तरक्की की है।

सुमन, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
पीएम गति शक्ति योजना

इसमें सुधार की काफी गुंजाइश बाकी

देश की बुनियादी सुविधाओं को हरसंभव बेहतर बनाने और विकास-योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आज से तीन साल पहले पीएम गति शक्ति योजना शुरू की थी, लेकिन जब तक राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अमल में नहीं लातीं, तब तक ऐसी कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। यह योजना कितनी कामयाब हुई, यह तो केंद्र सरकार ही जानती होगी और सबके इस पर अलग-अलग विचार भी हो सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिल-जुलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम कर रही होतीं, तो इस बार भी बरसात आम जन के लिए आफत नहीं बनती, सड़कों पर गड्ढे लोगों की जान के दुश्मन नहीं बनते। बीते रविवार को भी जालौर, पंजाब में सड़क पर गड्ढे ने एक बच्चे की जान ले ली। इतना ही नहीं, हमारे देश के कुछ शहर अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा सियासी भेदभाव व भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। कुछ सांसदों, विधायकों, पार्षदों और प्रधानों की भ्रष्टाचार करने की नीयत हमारे देश के कई इलाकों पर भारी पड़ रही है। इसी कारण आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी कई इलाके उचित विकास नहीं कर पाए हैं।

दावा किया जा रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है, लेकिन आज भी शहरों में लोगों का पानीपत भूख की वजह से होता है। रोजी-रोटी की तलाश में वे शहर आते हैं और वहीं के बन जाने की मजबूरी में अपना जीवन गुजार देते हैं। इनकी वजह से शहरों के बुनियादी ढांचे पर अप्रत्याशित भार बढ़ता है। नतीजतन, शहरों के आसपास या खाली क्षेत्रों में कंकरीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। इस अनियोजित विकास की कीमत पर्यावरण को भी चुकानी पड़ती है और मानवीय दखलंदाजी के कारण आबोहवा को काफी नुकसान पहुंचता है।

पीएम गति शक्ति का लाभ तभी पूरी तरह मिल सकेगा, जब शहरों में होते इस प्रवास और इसकी वजह से बढ़ती मुश्किलों का निदान हो। इसके लिए इस योजना में अपेक्षित सुधार की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, साल-दर-साल बढ़ते शहरों के प्रदूषण को भी नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे प्रयास होने चाहिए कि खेती की जमीनों का खेती-किसानी में ही इस्तेमाल हो, किसी अन्य काम में नहीं। महात्मा गांधी ने पर्यावरण और विकास पर समान रूप से जोर देने की वकालत की थी। हमें पीएम गति शक्ति में इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी यह योजना सार्थक नजर आएगी।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 15 अक्तूबर 2024

कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर पहला बड़ा कदम था। - आर्थर कीथ

बहराइच में धार्मिक जुलूस में जिस तरह से व्यवधान डालने की कोशिश की गई, उसकी पड़ताल और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसकी आड़ में समाजविरोधी तत्व फायदा न उठा पाएं।

हिंसा और संदेश

बहराइच जनपद के महाराजगंज इलाके में रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में हुई कहा-सुनी के बाद शुरू हुए हिंसा और तनाव के दौर का अगले दिन भी जारी रहना जितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उतनी ही क्षोभकारी है शुरुआती स्तर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बरती गई लापरवाही, जिसने माहौल को बिगड़ने का अवसर दिया। उल्लेखनीय है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस हर वर्ष इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन अब से पहले हिंसा हुई हो, ऐसा देखा नहीं गया था। इस बार जब घटनास्थल से जुलूस गुजर रहा था, तब पहले नारेबाजी और फिर दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव फैलता ही गया, जो वाकई चिंतित करने वाला है। त्योहार चाहे किसी भी धर्म के हों, उनका उद्देश्य समाज में खुशी, सामूहिकता और भाईचारे को बढ़ावा देना होता है। दुर्गा-पूजा भी भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन अवसरों का इस्तेमाल अपने निहित स्वार्थों के लिए करते हैं, जिससे समाज में तनाव व विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी घटनाएं सिर्फ बहराइच तक ही सीमित हों, ऐसा नहीं है। बीते रविवार को ही पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा-पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद, कर्नाटक और झारखंड में भी बीते दिनों ऐसी ही घटनाओं का होना सामाजिक ताने-बाने को हिला देने वाली गंभीर स्थितियों को ही दर्शाता है, जो राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों को भी धक्का पहुंचाती हैं। ये घटनाएं समाज को यह याद दिलाने की जरूरत की ओर इशारा करती हैं कि विविधता हमें तभी समृद्ध कर सकती है, जब हम इसका सम्मान कर सकें। लेकिन अगर यही विविधता, विभाजन की ओर अग्रसर होती है, तो यह न तो समुदाय विशेष और न ही राष्ट्रहित में होगा। बहराइच मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिखाई गई सख्ती ऐसे वक्त में बिल्कुल उपयुक्त

दिखती है, जिसके तहत उन्होंने आला अधिकारियों को मोर्चे पर उतारते हुए धार्मिक आयोजनों में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को तो कड़ा संदेश दिया ही है, लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की है। यही नहीं, धार्मिक संगठनों से संवाद कर प्रतिमा विसर्जन जारी रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी रणनीतिक संतुलन भी दर्शाया है। बहराइच में पैदा हुए माहौल के बहाने सामाजिक ताना-बाना नष्ट करने की ताक में बैठे तत्व सफल न हो पाएं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा और सामाजिक सद्भाव की रक्षा, इस वक्त प्रशासन के यही दो लक्ष्य होने चाहिए।

दो बीघा जमीन को याद कीजिए

किसी जमाने में बिमल रॉय की फिल्म *दो बीघा जमीन* में कर्ज से जूझते किसानों की जो स्थिति दर्शाई गई थी, आज किसानों और छोटे व्यवसायियों को उससे बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ता हैं और दोनों मिलकर जीडीपी में 40 फीसदी से अधिक का योगदान करते हैं।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रा की लागत और अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। हालांकि, पहली नजर में स्थितियां ब्याज दरों में कटौती का संकेत दे रही थीं। मुद्रास्फीति कम हो गई है, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक दरों में कटौती कर रहे हैं और जीडीपी वृद्धि दर रिजर्व बैंक के 7.1 प्रतिशत के पूर्वानुमान के मुकाबले 6.7 प्रतिशत पर धीमी रही। रिजर्व बैंक ने दरों में कटौती तो नहीं की, लेकिन अपने रुख को बदलकर तटस्थ कर दिया, जिससे निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का संकेत मिलता है। बहस पैसे की लागत और विकास की गति पर केंद्रित है। पैसे की कीमत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है ऋण तक व्यापक पहुंच। जैसा कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक *एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस* में लिखा है, 'पैसे से ही पैसा बनता है। जब आपके पास थोड़ा होता है, तो अक्सर और अधिक पाना आसान होता है। लेकिन, उस थोड़े से पैसे को पाना मुश्किल होता है।' भारत की अर्थव्यवस्था ऋण असमानता की लागत और छोटे व गरीब उधारकर्ताओं को कम ऋण देने की समस्या से त्रस्त है। मौजूदा परिदृश्य समस्याओं से भरा पड़ा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का ही उदाहरण ले लीजिए, भारत छह करोड़ एमएसएमई का घर है, उनमें से 2.97 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। एमएसएमई जीडीपी का 30 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 45 फीसदी और निर्यात का 48 फीसदी हिस्सा है, और वे करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ढेरों योजनाओं के बावजूद (जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसने कई एमएसएमई को बचाया और मुद्रा योजना) एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच कठिन बनी हुई है।

फरवरी, 2024 की क्रिसिल रिपोर्ट से पता चला है कि इस क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुंच मात्र 20 प्रतिशत है। 2022 में वित्त से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने पाया कि औपचारिक ऋण केवल

39 प्रतिशत एमएसएमई को ही छू पाया है। समिति ने यूके सिन्हा विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया, 'कुल मांग 37 लाख करोड़ रुपये के ऋण का अनुमान है, जबकि कुल आपूर्ति 14.5 लाख करोड़ रुपये है,' जिससे 20-25 लाख करोड़ रुपये का ऋण अंतर रह जाता है। फंडिंग की कमी एमएसएमई को प्रभावित करती है और प्रौद्योगिकी उन्नयन में बाधा डालती है।

दो बीघा जमीन समेत कई फिल्मों में ऋण के लिए किसानों के संघर्ष को दर्शाया गया है। उदारीकरण के 30 साल बाद भी कृषि लाइसेंस राज के अधीन है। खेती की व्यवहार्यता कानून, विनियमन और वितरण के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। कृषि के लिए बैंक ऋण 2014-15 के 6.04 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 24.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं और किसानों को ऋण लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2023 में हुए नाबार्ड के एक अध्ययन से पता चलता है कि 58 फीसदी किसान ऋण योजनाओं के बारे में जानते थे, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय है, लेकिन मात्र 28 फीसदी किसान ही ऋण ले पाते हैं। ऋण प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें जटिल प्रक्रिया, बैंक से दूरी और दस्तावेजीकरण शामिल हैं। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की ऋण से दूरी बनी हुई है। अध्ययन में बताया गया है कि बटाईदार किसानों को 'संस्थागत ऋण प्रणाली में शायद ही कभी शामिल किया जाता है।'

कृषि का जीडीपी में योगदान करीब 16 फीसदी है, जबकि इसमें 46 फीसदी कार्यबल लगे हुए हैं। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में 68 फीसदी भूस्वामियों के पास एक हेक्टेयर तक जमीन है। 2019 के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी और औसत घरेलू ऋण 74,121 रुपये। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि ने मदद की है, लेकिन इस क्षेत्र का संकट ग्रामीण खपत के आंकड़ों में दिखाई देता है और यह नौकरी में कोटे की मांग और हाल के चुनाव परिणामों में भी परिलक्षित होता है। किसानों की आय में सुधार और कृषि में कार्यबल के अनुपात को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिए ऋण का विस्तार करने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि वित्तीय समावेशन की कमी की वजह से ऋण वितरण में बाधा आ रही है। आधार ने जन-धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है। एक दशक में भारत ने 53.1 करोड़ लोगों को बैंक खातों से जोड़ा है, जिनमें से दो-तिहाई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। डिजिटल भुगतान में प्रौद्योगिकी की क्षमता स्पष्ट है-सितंबर में यूपीआई के जरिये 15 अरब लेनदेन हुए। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) लॉन्च किया। यूपीआई की तरह इससे ऋण दिया जा सकता है। हालांकि, नीति में खामियों के कारण ऋण तक पहुंच नहीं हो पाती है और बड़े उधारकर्ताओं को आसानी से ऋण देने को लेकर पूर्वाग्रह के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है। प्रौद्योगिकी तभी मदद कर सकती है, जब सिस्टम क्षेत्रों की क्षमता को पहचाने। ऋण मूल्यांकन खेती और छोटे व्यवसायों की व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, खेती की व्यवहार्यता इनपुट और बाजारों तक पहुंच पर निर्भर करती है, जो सामूहिक रूप से पैमाने और मूल्य प्राप्ति में सक्षम बनाती है। छोटे उद्यमी को तकनीक और पैमाने को उन्नत करने के लिए प्रणालीगत समर्थन और बड़े खरीदार द्वारा चूक से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सफलता के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसाय और किसान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। कृषि और एमएसएमई सबसे बड़े नियोक्ता हैं और दोनों मिलकर जीडीपी में 40 फीसदी से अधिक का योगदान करते हैं। विकास और समृद्धि को बनाए रखने के लिए ऋण अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। ऑटोमोटिव इंजीनियर बता सकते हैं कि सभी सिलेंडरों में ईंधन पहुंचाना रफ्तार और गति के लिए आवश्यक है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

होमी जे. भाभा

मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे 'सफल' आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने की कोई इच्छा नहीं है। कई लोग हैं, जो ऐसा करना पसंद करते हैं और यह उन्हें ही करने दें। यह मेरे स्वभाव से अलग है।

मेरा एक ही उद्देश्य है जीवन के प्रति चेतना बढ़ाना

मैं अपने जीवन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझे जीवन से क्या चाहिए। जीवन और मेरी भावनाएं ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में मैं सचेत हूं। मुझे जीवन की चेतना से प्यार है और इसे जितना संभव हो सके, उतना प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन हर किसी के जीवन की अवधि सीमित होती है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह कोई नहीं जानता। न ही मुझे इसकी परवाह है। चूंकि मैं जीवन की अवधि नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है- जीवन के प्रति अपनी चेतना की तीव्रता को बढ़ाना, क्योंकि जीवित रहना मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेरणा है।

एक बार मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे 'सफल' आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने की कोई इच्छा नहीं है। कई बुद्धिमान लोग हैं, जो ऐसा करना पसंद करते हैं और उन्हें ही ऐसा करने दें। इंजीनियर की नौकरी और व्यवसाय मेरे लिए नहीं है। यह मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग और विचारों के विपरीत है। मेरा क्षेत्र भौतिकी है, और मुझे पता है कि मैं यहां सबसे बेहतर कार्य करूंगा। हर व्यक्ति केवल उसी चीज में सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ हो सकता है, जिसके लिए वह जुनूनी है, जिसमें वह विश्वास करता है, जैसा कि मैं करता हूं। मैं भौतिकी के क्षेत्र में काम करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित हूं। मैं इसे कभी न कभी करूंगा और मुझे इसे करना ही होगा। यह मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है। और आखिर में मैंने इसे किया।

मैंने एक बात शुरू से सीखी है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने काम से क्या बनाता हूं। मैं फिलहाल भौतिकी की मौलिक समस्याओं को देखता हूं। हालांकि, पूरे भारत में ऐसे सक्षम कार्यकर्ता हैं, जो उचित निर्देशन और सुविधाओं के अभाव की वजह से उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना वे कर सकते हैं। आज भारत में किए जाने वाले अधिकांश शोध निराशाजनक हैं, तो इसका कारण यह है कि पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट शोधकर्मियों की कमी है। भारत में वैज्ञानिक संस्थान, चाहे वह प्रयोगशाला हो या अकादमी, उसे एक पेड़ की तरह बहुत सावधानी से विकसित किया जाना चाहिए। हमारे जीवन में विज्ञान का होना बेहद जरूरी है। इसलिए जर्मन संगीतकार और पियानोवादक लुडविग वान बीथोवेन ने यह कहा था कि आपको वैज्ञानिक बनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है, जबकि उन्हें विज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। सुकरात ने भी कहा था कि 'इंजीनियर बनो, यह बुद्धिमान व्यक्ति का काम है', जबकि ये चीजें उनकी प्रकृति में भी नहीं थीं।

दूर की नहीं, पास की सुनें!

सूत्र

अपनी आवाज, अपनी आत्मा की सुनें। बहुत से लोग खुद के बजाय दुनिया के शोर को सुनते हैं। एक बार जब आप स्वयं को सुनने के आदी हो जाते हैं, तो हमारा पूरा शरीर एक संगीत वाद्ययंत्र की तरह प्रतिक्रिया करता है। और आप जब दिल की सुनते हैं और किसी कार्य के प्रति जुनूनी होते हैं, तो जीवन को सही ढंग से जीने लगते हैं।

दूसरा पहलू

कई तरह की छूट की घोषणा के बावजूद हांगकांग में पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।

हांगकांग को क्यों नहीं मिल रहे पर्यटक?

हवाई कंपनियां हांगकांग के लिए पर्यटकों को छूट दे रही हैं। वहां पर्यटकों के लिए ड्रोन और दूसरे एअर शो हो रहे हैं। हांगकांग ने सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को अपने यहां आमंत्रित किया है कि वे आकर देश की खूबसूरती देखें और इसकी कहानी बताएं। इसके बावजूद हांगकांग को पर्यटक नहीं मिल रहे, तो यह आश्चर्य की ही बात है।

दरअसल, एक समय पर्यटन व्यवसाय ही हांगकांग की आर्थिक ताकत था। लेकिन कोविड और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वहां पर्यटकों की संख्या जो घटी, उसमें अब भी वृद्धि नहीं हो पा रही। हांगकांग के लिए परेशानी की बात यह भी है कि थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे एशियाई देशों में पर्यटकों का आंकड़ा कोविड से पहले के स्तर पर आ गया है। लंबे समय से पर्यटकों की कमी के कारण हांगकांग की छोटी-छोटी असंख्य दुकानें और रेस्तरां बंद हो गए हैं। जबकि बड़े होटलों में किसी भी समय दर्जनों कमरे खाली पाए जाते हैं।

क्रिस्टिन चुंग

ग्राहकों की कमी से छोटी दुकानों और रेस्तरां को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मार्च से अगस्त के बीच देश में लगभग 1,000 रेस्तरां बंद हो गए हैं।

वर्ष 2019 में चीन के वर्चस्ववाद के खिलाफ हांगकांग में हुए जनांदोलन के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा।

हांगकांग की इस बदहाली के कई कारण बताए जा रहे हैं। वर्ष 2019 में चीन के वर्चस्ववाद के खिलाफ हांगकांग में हुए जनांदोलन के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा। उस साल के उत्तरार्ध में वहां पर्यटकों के आंकड़े में 2018 की तुलना में 40 फीसदी की कमी आ गई। वर्ष 2020 में कोविड से निपटने के लिए हांगकांग ने अपनी सीमाएं सील कर दी थीं। और अब भारी संख्या में विदेशी नागरिकों और कंपनियों के बाहर निकल जाने से लंबे समय से वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग की जो छवि बनी थी, उसे धक्का लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में खाना और शॉपिंग करना महंगा होने के कारण हांगकांग के स्थानीय लोग शॉपिंग करने और यहां तक कि भोजन करने तक के लिए सीमा पार कर चीन पहुंच रहे हैं।

ग्राहकों की कमी से छोटी दुकानों और रेस्तरां को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हांगकांग फेडरेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स ऐंड रिलेटेड ट्रेड्स के प्रमुख सिमॉन वांग का-वो के अनुसार, ग्राहकों के अभाव में मार्च से अगस्त के बीच देश में लगभग 1,000 रेस्तरां बंद हो गए हैं। वान चाई में कई जापानी रेस्तरां चलाने वाले केविन शीह कहते हैं, बार में पहले से बहुत कम लोग दिखते हैं और देर रात गलियों में घूमने वाले लोग भी बहुत कम हैं। मैं मानता हूं कि हांगकांग कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तकदीर नहीं सुधरी है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

चाय उत्पादन

भारत के चाय उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान असम का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल एवं अन्य राज्यों का स्थान है।

असम	49.39%
पश्चिम बंगाल	31.10%
तमिलनाडु	12.01%
केरल	4.57%
अन्य राज्य	2.91%

आंकड़े वर्ष 2023 के

स्रोत : Tea Board

स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र को समझाया कि यह सही है कि बाघ में परमात्मा हैं, तो उससे क्यों डरें, लेकिन उससे दूर रहने के लिए चेताने वाले में भी तो परमात्मा हैं।

सब में परमात्मा

रविवार की दोपहर थी। रामकृष्ण परमहंस का कमरा भक्तों और अनुयायियों से ठसाठस भरा हुआ था। स्वामी जी 19 वर्ष के एक लड़के के साथ बड़े प्रेमपूर्वक बातचीत कर रहे थे। लड़के का नाम था- नरेंद्र। अभी वह कॉलेज में ही पढ़ रहा था। वह कभी-कभी ब्रह्म समाज में जाता था और कभी-कभी स्वामीजी से भी भेंट किया करता था।

रामकृष्ण ने उससे पूछा, 'क्यों नरेंद्र ! तू संसार के लोगों के बारे में क्या कहेगा? सांसारिक लोग तो भक्त को पागल समझते हैं। यदि कोई तेरी निंदा करे, तो तू क्या सोचेगा उसके बारे में?

नरेंद्र ने जवाब दिया, 'जब हाथी सड़क से जाता है, तो उसके पीछे कितने ही श्वान भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी पलटकर भी उनकी तरफ नहीं देखता। इसलिए मैं तो यही सोचूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं।' रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हुए कहा, 'अरे नहीं! इतना नीचे मत सोचो। (वहां उपस्थित सभी लोग हंस देते हैं।) सभी जीवों में परमात्मा का वास है। सभी से प्रेम करना चाहिए।'

अंतर्यात्रा
संकलित

नरेंद्र ने उनसे पूछा, 'बाघ में भी परमात्मा का वास है, तो क्या बाघ को भी गले से लगा लेना चाहिए?' फिर सभी लोग हंस पड़े। रामकृष्ण ने समझाया, 'हां, सही है कि बाघ में परमात्मा हैं, तो बाघ से क्यों डरें? लेकिन जो लोग बाघ से सावधान रहने के लिए कहते हैं, उनमें भी तो वही परमात्मा है, तो उनकी भी बात क्यों न मानें!' नरेंद्र एवं सभी भक्त स्वामीजी की बात बखूबी समझ गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 28 दिसंबर, 1960

बेल्जियम में सरकार हड़ताल के आगे नहीं झुकेगी

बेल्जियम में सरकार हड़ताल के आगे नहा झुकेगी

बेल्जियम सरकार ने मितव्ययिता नीति में कोई परिवर्तन न करके और हड़ताल के आगे न झुकने का निश्चय किया है। सरकार मितव्ययिता योजना को रद्द नहीं करेगी। वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।

किसी को बधाई, किसी को जहर

बधाई या आभार जताने वाले होर्डिंग खतरनाक तत्वों से बने होते हैं। फिर कूड़े के ढेर में पहुंचकर ये हवा को बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं।

विवेक एस अग्रवाल

मुद्दा

भारत के दक्षिणी राज्यों से प्रारंभ हुई व्यक्ति पूजा और स्वयं के प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक स्थलों पर छोटे-बड़े महिमामंडन के बैनर-पोस्टर और होर्डिंग लगाने की परंपरा अब न सिर्फ शहरों में, बल्कि गांवों तक पहुंच गई है। इसमें निरंतर प्रतिस्पर्धा के चलते एक-दूसरे से अधिक संख्या और बड़े आकार के विज्ञापन लगा कर अपने कद को बड़ा साबित करने के प्रयास किए जाते हैं। यह होड़ शहरों के लिए न सिर्फ बदनुमा धब्बे का रूप ले रही है, बल्कि उससे भी अधिक बुरी बात है कि वातावरण में जहर घोलने का काम भी कर रही है, जिसका एतबार न लगाने वाले को, न प्रायोजित करने वाले को है। मासूम जनता तो मानो पूर्ण अनभिज्ञता के साथ जो हो रहा है, उसे स्वीकार कर रही है।

यों तो हर राज्य और शहर के लिए विज्ञापन संबंधी नियम-कायदे बने हुए हैं, जो निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त कहीं पर भी प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं, किंतु अनाधिकृत प्रदर्शित विज्ञापन

सामग्री पर यदा-कदा ही कार्रवाई हो पाती है।

इस प्रकार के बधाई संदेशों का चलन इतना बढ़ गया है कि इन्हें सार्वजनिक उत्पात की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अधिक से अधिक व्यक्तियों की दृष्टि में आने की लालसा में ये विज्ञापन होर्डिंग्स सड़क हादसों के लिए भी अनेक बार उत्तरदायी होते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर गंदगी भी एकत्रित करते हैं। बढ़ते प्रदर्शन के दौर में जन्मदिन, बधाई, शुभकामना, आभार आदि संबंधी छोटे-बड़े होर्डिंग बेशुमार मात्रा में लगाए जाते हैं, जिनसे संबंधित व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, बिना यह जाने कि उस संदेश को विज्ञापित करने वाली सामग्री कितनी जहरीली है। इन सामग्रियों के संपूर्ण वातावरण पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। प्रयुक्त सामग्री का किसी भी प्रकार से पुनः उपयोग नहीं हो पाता है और उसका जहां भी निष्पादन होता हैं, वहां वह वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह बन जाती है।

पिछले दिनों दशहरे पर हमने देखा कि आजकल लग रहे बधाई पट्ट रावण जैसे पुतले बनाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं बढ़ते रावण पुतला निर्माण में बढ़ते बधाई संदेश ही तो मददगार नहीं हैं? वैसे भी प्रयुक्त किया जाने वाला पीवीसी सामग्री रावण जैसी असुरी प्रवृत्ति से कम भी नहीं है। बधाई संदेश में लगे बांस और खपच्ची रावण का ढांचा बना देते हैं और उपयोग में लाया गया सिंथेटिक पॉलीमर उसकी भराई और ऊपरी सतह की तरह काम में उपयोग किया जाता है। जब यह पुतला जलता है, तो इससे खतरनाक डाइऑक्सिन वातावरण में घुल जाता है। यह तत्व सबसे जहरीले तत्वों में शुमार है, जो पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार, 80 प्रतिशत डाइऑक्सिन प्रदूषण के लिए पीवीसी ही दोषी है। कार्बन शृंखला का उत्पाद होने के कारण पीवीसी के द्वारा कार्बन उत्सर्जन भी अत्यधिक मात्रा में होता है। मूल सामग्री के अतिरिक्त उक्त प्रदर्शन सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त रंगों के अतिरिक्त भी रसायन उपयोग में लिए जाते हैं, जो मानवीय एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होते हैं। आजकल स्टार फ्लेक्स प्रिंटिंग का भी चलन है, जो कि आमतौर पर उपयोग में लिए जाने वाले पीवीसी से मोटा होता है, किंतु उसका निष्पादन भी जटिल रहता है।

इनका चलन इसलिए भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी लागत मात्र दस रुपये प्रति फीट आती है और एक होर्डिंग चार सौ से छह सौ रुपये में तैयार हो जाता है। इनको प्रदर्शित करने का कोई भी शुल्क या कर नगरीय निकाय द्वारा वसूल नहीं किया जाता, जबकि निर्धारित स्थल के विज्ञापन नीलामी के जरिये एक तय मासिक या वार्षिक राशि के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। यदि प्रदर्शित सामग्री का उपयोग जलाने या ढकने में नहीं होता, तो वह कचरा डिपो में पहुंच जाती है और प्रदूषण की नई शृंखला प्रारंभ कर देती है।

खुला कचरा अपने आप में वायुमंडल के लिए अभिशाप है, उसके ऊपर यह सामग्री तड़के का काम करती है। यदि यह कचरा घर तक पहुंच जाए, तो मीथेन जैसी विषैली गैस के उत्सर्जन में उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है।

महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या आम जनता की सेहत और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हुए बधाई संदेशों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। क्या यही शक्ति प्रदर्शन का एकमात्र आधार है? यदि इनके प्रदर्शन पर शुल्क लगता या कोई कार्रवाई होती, तो संभवतया इन पर अंकुश लग सकता था। बधाई-आभार संबंधी सार्वजनिक प्रदर्शित विज्ञापन के उत्पात को रोकने के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहिए और उसे लगाने वाले पर दंड भी लागू करना चाहिए, अन्यथा यह चलन बढ़ता ही जाएगा और वातावरण भी जहरीला होता जाएगा।